सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 284, नई दिल्ली । सोमवार, 23 दिसम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे।

03 दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लगते ही फ्लाइंग स्क्वायड हो जाएगा सक्रिय
06 राष्ट्रीय गणित दिवस 2024: अन्वेषण करें, सीखें और प्रेरित हों
08 साम्बादिक रूबेन बानार्जी ने पांडियन का गोंद खोला

दिल्ली चुनाव में सार्वजनिक परिवहन सेवा बड़ा मुद्दा, बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत

दिल्ली विधानसभा चुनाव में सार्वजनिक परिवहन एक बड़ा मुद्दा है। दिल्ली सरकार ने अगले साल तक बसों का बेड़ा 10 हजार तक करने का लक्ष्य रखा है लेकिन कैलाश गहलोत के आप छोड़ने के बाद इलेक्ट्रिक बसों के अभियान को झटका लगा है। इस साल जनवरी से अभी तक 225 बसें घट चुकी हैं। भाजपा और आप सरकार के बीच बसों की उपलब्धता को लेकर राजनीति गर्माती रही है।

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवा बड़ा मुद्दा है, इससे जहां आवागमन आसान होगा वहीं प्रदूषण पर भी लगाम लगाने में कुछ मदद मिलेगी। दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों के धुएं का हिस्सा ज्यादा है, ऐसे में जोर दिया जाता है कि सार्वजनिक परिवहन सेवा मजबूत की जाए, जिससे सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम हो सके। हालांकि ये हो नहीं पा रहा है।

हर विधानासभा चुनाव में राजनीतिक दल परिवहन सेवा को बेहतर बनाने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। वर्तमान हालात ये हैं कि दिल्ली जितनी नई आ रहीं हैं, उससे अधिक सड़कों से हट रहीं है। तमाम प्रयासों के बाद भी सार्वजनिक बस सेवा की कमी पूरी नहीं हो रही।

दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ रहा असर

नतीजतन पुरानी बसें भी चलाई जा रही हैं, जो रास्ते में खराब हो जाती हैं। बसों की कमी का शहर की यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। बसें कम होने के चलते लोग निजी वाहनों का ले रहा हैं सहारा, इससे सड़कों पर जाम लगता है, जिससे लोग परेशान होते हैं।

आप के इलेक्ट्रिक बसों के अभियान को झटका

दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि अगले साल तक बसों का बेड़ा 10 हजार तक किया जाए। मगर परिवहन मंत्री के रूप में अपनी पहचान बना चुके कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी छोड़ने के साथ ही आने वालीं इलेक्ट्रिक बसों के अभियान को झटका लगा है। 30 जुलाई के बाद से एक भी नई इलेक्ट्रिक बस बेड़े में शामिल नहीं हुई है।

इस साल घट चुकी हैं 225 बसें

दिल्ली की सड़कों से पुरानी बसों को हटाने का क्रम अगले माह से और तेज होने जा रहा है। अक्टूबर से दिसंबर तक ही सड़कों से डीटासी की 394 बसें और हट जाएंगी। अभी तक किसी तीन माह में बसों के घटने की यह सबसे बड़ी संख्या होगी। इस साल जनवरी से अभी तक 225 बसें घट चुकी हैं। यानी सड़कों से डीटीसी की 619 बसें हट रही हैं।

वहीं वर्ष 2025 में बसों के हटने का असर ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि डीटीसी की 2,000 से अधिक बसें हट जाएंगी वहीं वर्ष 2026 तक 3,775 बसें हट जाएंगी। सार्वजिक परिवहन के मामले में दिल्ली की जनता सरकार को इस नजर से देख रही है कि कब पर्याप्त बसें होंगी और समय पर मिल सकेंगी। उम्मीद है कि आने वाले सालों में शायद सार्वजनिक परिवहन सेवा बेहतर हो सके।

भाजपा और आप सरकार के बीच गर्माती रही है राजनीति

दिल्ली में बसों की उपलब्धता को लेकर राजनीति गर्माती रही है। भाजपा इसे लेकर पिछले 10 साल से आप सरकार को घेरती रही है। पर्याप्त बसें उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाती रही है। आप भी भाजपा पर एलजी के माध्यम से काम न करने देने का आरोप लगाती रही है।

करीब चार साल पहले भाजपा द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाने पर दिल्ली सरकार की ओर से खरीदी जा रहीं 1,000 सीएनजी बसों पर रोक लग गई थी। भाजपा ने आरोप लगाया था कि जितनी कीमत की बसें हैं, उससे चार गुना ज्यादा पैसा टेंडर में इन बसों के रखरखाव के लिए निर्धारित किया गया है।

इसके बाद एलजी ने मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी थी और बसों के इस टेंडर को रद कर दिया था। इस सब के बीच भाजपा अभी भी आरोप लगा रही है कि सार्वजनिक परिवहन के मामले में आप सरकार फेल साबित हुई है।

रोजाना सड़क पर ही खराब हो जाती हैं 500 बसें

बसें इतनी कम हैं कि दिल्ली के ही नहीं एनसीआर के कई रूटों पर भी बसें कम हो गई हैं। बसों में सफर से लोगों का भरोसा उठ चुका है कि वे अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच सकेंगी या रास्ते में खराब नहीं होंगी। दिल्ली की स्थिति आज ऐसी है कि औसतन प्रतिदिन 500 बसें सड़क पर ही खराब हो जाती हैं, क्योंकि अधिकतर बसें पुरानी हैं।

अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वर्षों में हालात बदलेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अपने बेड़े में अब सभी बसें इलेक्ट्रिक की रखने का फैसला लिया है। ऐसा पहली बार है, जब डीटीसी की अधिकतर लो-फ्लोर सीएनजी बसों ने परिचालन सीमा को पार कर लिया है।

डीटीसी आठ साल से अधिक समय तक चलने के बाद बस को ओवरएज के रूप में घोषित कर देती है। लो-फ्लोर सीएनजी बस का अधिकतम परिचालन जीवन 12 वर्ष या साढ़े सात लाख किमी निर्धारित है।

इन कंपनियों की हैं बसें

टाटा	2682
अशोक लीलेंड	1093

पुरानी को सड़कों से हटाना तेज, नई बसों का आना है धीमा

जितनी तेजी से पुरानी बसों को दिल्ली की सड़कों से हटाया जा रहा है, उनती तेजी से नई बसें आने का सिलसिला नहीं दिख रहा है। इससे सरकार के सामने चुनावी साल में दिल्ली में जनता को पर्याप्त बसें उपलब्ध कराने की चुनौती बढ़ रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि अगले साल तक दिल्ली के बेड़े में 10 हजार बसें होंगी। जिसमें 80 प्रतिशत इलेक्ट्रिक होंगी।

सरकार के अनुसार जल्द ही 1,080 मोहल्ला बसें सड़कों पर उतरने वाली हैं। इनमें से 150 बसें दिल्ली में आ चुकी हैं और मुख्यमंत्री आतिशी इन बसों का निरीक्षण भी कर चुकी हैं, मगर ये बसें कब सड़कों पर उतरेंगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। वर्तमान में डीटीसी की 4,536 बसें सड़कों पर हैं। जिसमें 2,966 सीएनजी और 1,570 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं।

दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-माडल ट्रांजिट सिस्टम की ओर से 3,147 बसें चल रही हैं। जिसमें 2,747 सीएनजी और 400 इलेक्ट्रिक बसें हैं। दोनों को मिला लें तो दिल्ली सरकार के बेड़े में इस समय 7,683 बसें हैं। जबकि दिल्ली में सार्वजनिक बसों की बात करें तो 11 हजार बसों की जरूरत है।

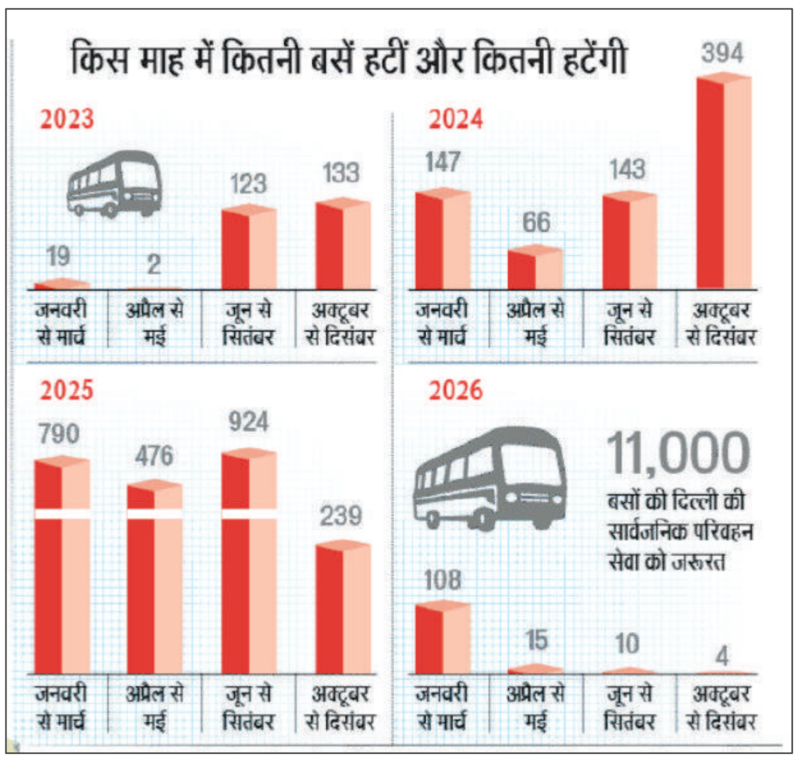

दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाली बसों के लिए तय होंगे बस अड्डे, परिवहन विभाग ने तैयार की योजना

परिवहन विशेष न्यूज

इसके तहत अब अलग-अलग राज्यों से आने वाली बसें के रुकने और चलने के लिए बस अड्डे तय किए जाएंगे।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में अंतरराज्यीय सरकारी बसों की आवाजाही को दुरुस्त करने के लिए परिवहन विभाग की ओर से योजना तैयार की गई है। इसके तहत अब अलग-अलग राज्यों से आने वाली बसें के रुकने और चलने के लिए बस अड्डे तय किए जाएंगे।

मौजूदा समय में दिल्ली के तीनों बस अड्डों कश्मीरी गेट, आनंद विहार और सराय काले खां पर सभी राज्यों की बसें शुरू और समाप्त होती हैं। ऐसे में सड़कों पर यातायात दबाव बढ़ता है। परिवहन विभाग की योजना है कि जिस तरह से दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर दिशा के अनुसार राज्यों में जाने वाली ट्रेन मिलती है उसी तरह से बस अड्डों पर राज्य वार बसें शुरू हो और समाप्त हो। इसके लिए निश्चित राज्य से आने वाली बसों के लिए एक समर्पित बस अड्डा तय किया जाएगा।

परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि योजना यह है कि हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर समेत उत्तरी राज्यों की बसें कश्मीरी गेट बस अड्डे पर रुकेंगी। जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार समेत अन्य पूर्वी राज्यों की बसें आनंद विहार बस अड्डे पर रुकेंगी। वहीं दक्षिणी राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों की बसें सराय काले खां बस अड्डे पर रुकेंगी। इससे दिल्ली की सड़कों पर बसों का भार कम होगा।

यह योजना निजी और सरकारी अंतरराज्यीय बसों पर लागू होगी। मौजूदा समय में सभी राज्यों की बसें सभी बस अड्डों पर आती हैं। ऐसे में उन बसों से यातायात पर असर होता है। योजना के अमलीजामा पहनाने के लिए अभी नोटिस जारी कर सुझाव मांगा गया है। 15 दिन के भीतर मिले सुझाव पर योजना लागू की जाएगी। बता दें कि इससे पहले परिवहन विभाग ने निजी बस ऑपरेटरों के लिए दिशा निर्देश तय किए थे। इसमें कहा गया था कि निजी बसें दिल्ली के तीनों आईएसबीटी पर ही सवारियों को पिक और ड्रॉप करेंगी। इससे न केवल सड़कों पर निजी बसों की वजह से लगने वाला जाम खत्म होगा बल्कि दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगेगी।

अंतरराज्यीय बस अड्डे दिल्ली में हैं इनसे चलती हैं सभी राज्यों की बसें

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आईएसबीटी कश्मीरी गेट, आनंद विहार और सराय काले खां पर पहले से अब बसों के रुकने के समय को कम किया गया है, साथ ही अन्य सुविधाओं को भी बढ़ाया है।

3000 से अधिक अंतरराज्यीय बसों की होती है आवाजाही

अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली में रोजाना 3000 से अधिक सरकारी बसों की आवाजाही होती है। इसमें सबसे अधिक कश्मीरी गेट बस अड्डे से रोजाना 1500-1600 बसें चलती हैं। वहीं अक्तूबर, नवंबर और मार्च के त्योहारी महीनों के दौरान यह संख्या बढ़कर 1750 बसें रोजाना हो जाती हैं। वहीं आनंद विहार में प्रतिदिन 800-850 बसें आती हैं और त्योहारों के समय यह संख्या एक हजार होती है।

जबकि सराय काले खां में प्रतिदिन औसतन 200-260 बसें आती हैं। अधिकारियों का कहना है कि नई योजना के तहत बस अड्डों से योजनाबद्ध तरीके से बसों की राज्य वार आवाजाही होगी। इससे यात्रियों को यह पता होगा कि अगर उन्हें किसी खास राज्य के लिए बस पकड़नी है तो उन्हें किस बस अड्डे पर जाना है।

इसका शुभारंभ शनिवार को एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन पर किया

नमो भारत ट्रेन के सफर में मिलेगी 10% की छूट

एनसीआरटीसी ने आरआरटीएस कनेक्ट प्रोग्राम शुरू किया

परिवहन विशेष न्यूज

यात्रियों के साथ जुड़ने और उन्हें नमो भारत ट्रेन के टिकट पर 10 फीसदी की छूट देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने आरआरटीएस कनेक्ट मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से लॉयल्टी पॉइंट्स प्रोग्राम की शुरुआत की है।

यात्रियों के साथ जुड़ने और उन्हें नमो भारत ट्रेन के टिकट पर 10 फीसदी की छूट देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने आरआरटीएस कनेक्ट मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से लॉयल्टी पॉइंट्स प्रोग्राम की शुरुआत की है।

इसका शुभारंभ शनिवार को एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन पर किया। इस दौरान द्वि-मासिक यात्री न्यूजलेटर नमो भारत टाइम्स के पहले संस्करण का अनावरण भी किया गया।

लॉयल्टी पॉइंट्स प्रोग्राम के तहत यात्रियों को नमो भारत ट्रेन टिकट पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपये के बदले 1 अंक प्राप्त होगा। प्रत्येक लॉयल्टी पॉइंट का मूल्य 0.10 (10 पैसे) है और इसे यात्रियों के आरआरटीएस कनेक्ट खाते में जमा किया जाएगा।

इन पॉइंट्स का प्रयोग भविष्य में टिकट खरीदने के लिए किया जा सकेगा। इस पहल से न केवल यात्रियों को आर्थिक लाभ होगा, बल्कि आरआरटीएस कनेक्ट एप के माध्यम से डिजिटल क्यूआर टिकट के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। पेपरलेस टिकटिंग के माध्यम से यह यात्रा को भी सरल बनाएगा।

'आरआरटीएस कनेक्ट' एप डाउनलोड करने वाले प्रत्येक नए उपयोगकर्ता को 500 लॉयल्टी पॉइंट दिए जा रहे हैं। यात्री 'आरआरटीएस कनेक्ट' एप को अन्य उपयोगकर्ताओं को रेफर करके अतिरिक्त 500 लॉयल्टी पॉइंट भी अर्जित कर सकते हैं।

रेफर करने वाले और जिसे रेफर किया गया है, दोनों को 500 लॉयल्टी पॉइंट प्राप्त होंगे। सभी अर्जित लॉयल्टी पॉइंट क्रेडिट होने की तारीख से एक वर्ष तक वैध रहेंगे। वहीं द्वि-मासिक न्यूज़लेटर, नमो भारत टाइम्स, एनसीआरटीसी के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। इसमें 'आरआरटीएस कनेक्ट' एप भी शामिल है।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

भारत में बुज़ुर्ग आबादी की समस्याएँ

भारत अपने जनसांख्यिकीय परिवर्तन के एक अनोखे चरण में है। भारत की विशेषता है कि यहाँ युवा आबादी में वृद्धि हो रही है, जो विकास को गति देने के लिए एक अवसर हो सकता है। हालाँकि, एक समानांतर घटना जिस पर भारत के आर्थिक विकास के संदर्भ में समान रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है तेज़ी से बढ़ती उम्र, यानी बढ़ती बुज़ुर्ग आबादी। बुढ़ापा एक सतत, अपरिवर्तनीय, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जो गर्भधारण से लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक चलती है। हालाँकि, जिस उम्र में किसी व्यक्ति का उत्पादक योगदान कम हो जाता है और वह आर्थिक रूप से निर्भर हो जाता है, उसे संभवत: जीवन के बुज़ुर्ग चरण की शुरुआत माना जा सकता है। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के अनुसार, एक वरिष्ठ नागरिक का अर्थ भारत का नागरिक होने वाला कोई भी व्यक्ति है जो साठ वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर चुका है। भारत जैसा जनसांख्यिकीय रूप से युवा देश धीरे-धीरे बूढ़ा हो रहा है। 2050 तक भारत में हर 5 में से 1 व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु का होगा। दुनिया की बुज़ुर्ग आबादी में से 1 / 8वां हिस्सा भारत में रहता है।

--डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत की आबादी में वरिष्ठ नागरिकों का प्रतिशत हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ रहा है और यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है, ऐसा संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव के अनुसार है। कम आय या ग़रीबी को बुज़ुर्गों के साथ दुर्व्यवहार से जुड़ा पाया गया है। कम आर्थिक संसाधनों को बुज़ुर्गों के साथ दुर्व्यवहार में योगदान देने वाले एक प्रासंगिक या परिस्थितिजन्य तनाव के रूप में माना जाता है। बैंक जमा पर लगातार गिरती ब्याज दरों के कारण, अधिकांश मध्यम वर्ग के बुज़ुर्ग वास्तव में ख़ुद को बनाए रखने के लिए बुज़ुर्ग पेंशन पर निर्भर हैं।

भारत में, 74% बुज़ुर्ग पुरुष और 41% बुज़ुर्ग महिलाओं को कुछ व्यक्तिगत आय प्राप्त होती है, जबकि 43% बुज़ुर्ग आबादी कुछ भी नहीं कमाती है। व्यक्तिगत आय प्राप्त करने वाले 22% बुज़ुर्ग भारतीयों को प्रति वर्ष 12, 000 रुपये से कम मिलता है। जैसे-जैसे बुज़ुर्ग लोग काम करना बंद कर देते हैं और उनकी स्वास्थ्य देखभाल की ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं, सरकारें अभूतपूर्व लागतों से अभिभूत हो सकती हैं। हालांकि कुछ देशों में जनसंख्या की उम्र बढ़ने के बारे में आशावादी होने का कारण हो सकता है, लेकिन प्यू सर्वेक्षण से पता चलता है कि जापान, इटली और रूस जैसे देशों के निवासी बुढ़ापे में पर्याप्त जीवन स्तर प्राप्त करने के बारे में सबसे कम आश्वस्त हैं। एनजीओ हेल्पएज इंडिया द्वारा किए गए एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण से पता चला है कि 47% बुज़ुर्ग लोग आय के लिए आर्थिक रूप से अपने परिवारों पर निर्भर हैं और 34% पेंशन और नकद हस्तांतरण पर निर्भर हैं, जबकि सर्वेक्षण में शामिल 40% लोगों ने ₹जितना संभव हो सके₹ काम करने की इच्छा व्यक्त की है। भारत में पाँच में से एक बुज़ुर्ग व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याओं से ग्रस्त है। उनमें से लगभग 75 प्रतिशत किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं और 40 प्रतिशत

को कोई अन्य विकलांगता है। ये 2021 में लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया के निष्कर्ष हैं।

वृद्ध लोग शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की उम्र बढ़ने के कारण अपक्षयी और संचारी दोनों तरह की बीमारियों से पीड़ित होते हैं। रुग्णता के प्रमुख कारण संक्रमण हैं, जबकि दृष्टि दोष, चलने, चबाने, सुनने में कठिनाई, ऑस्टियोपोरोसिस, गठिया और असंयम अन्य सामान्य स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याएँ हैं।

किफ़ायती नर्सिंग होम या सहायता प्राप्त रहने वाले केंद्रों की ज़रूरत वाले बीमार और कमज़ोर बुज़ुर्गों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों में वृद्धावस्था देखभाल सुविधाओं का अभाव। हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 30% से 50% बुज़ुर्ग लोगों में ऐसे लक्षण थे जो उन्हें उदास कर देते थे। अकेले रहने वाले बुज़ुर्गों में से ज़्यादातर महिलाएँ हैं, ख़ास तौर पर विधवाएँ। अवसाद का गरीबी, खराब स्वास्थ्य और अकेलेपन से गहरा सम्बंध है। वयस्कों के औपचारिक नौकरियों में और बच्चों के स्कूल की गतिविधियों में व्यस्त होने के कारण, बुज़ुर्गों की देखभाल करने के लिए घर पर कोई नहीं रहता। पड़ोसियों के बीच सम्बंध ग्रामीण क्षेत्रों की तरह मज़बूत नहीं हैं। आर्थिक तंगी उन्हें रचनात्मकता को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देती। परिवार के सदस्यों की उपेक्षा के कारण कई लोग बच्चों के साथ रहने के बजाय डे केयर सेंटर और वृद्धाश्रम को प्राथमिकता देते हैं।

बुज़ुर्गों के साथ दुर्व्यवहार एक बढ़ती हुई अंतरराष्ट्रीय समस्या है जिसकी विभिन्न देशों और संस्कृतियों में कई अभिव्यक्तियाँ हैं। यह मानवाधिकारों का एक मौलिक उल्लंघन है और इससे कई स्वास्थ्य और भावनात्मक समस्याएँ पैदा होती हैं। दुर्व्यवहार को शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक या वित्तीय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, बुज़ुर्ग महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के बीच दुर्व्यवहार अपेक्षाकृत अधिक होता है। लगभग आधे बुज़ुर्ग दुखी और उपेक्षित महसूस करते हैं; 36 प्रतिशत को लगता है कि वे परिवार के लिए बोझ हैं। मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार से होने वाली भावनात्मक क्षति में यातना, दुख, भय, विकृत भावनात्मक असुविधा और व्यक्तिगत गौरव या संप्रभुता की हानि शामिल है।

सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर पर, वृद्ध व्यक्ति को कमज़ोर और आश्रित के रूप में प्रस्तुत करना, देखभाल के लिए पैसे की कमी, सहायता की ज़रूरत वाले बुज़ुर्ग लोग जो अकेले रहते हैं और परिवार की पीढ़ियों के बीच सम्बंधों का टूटना, बुज़ुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के संभावित कारक हैं। आर्थिक समस्याओं के कारण निम्न जाति के बुज़ुर्गों को बुढ़ापे में भी आजीविका के लिए काम करना पड़ता है। हालांकि यह मुश्किल है, लेकिन यह उन्हें सक्रिय रखता है, आत्म-सम्मान की भावना बनाए रखता है और परिवार से सम्मान प्राप्त करता है। जबकि उच्च जाति के बुज़ुर्गों के लिए, अच्छी नौकरियाँ कम उपलब्ध होती हैं और वे छोटी-मोटी नौकरियाँ करने में संकोच करते हैं। यह उन्हें बेरोज़गार बनाता है, इसलिए 'बेकार' होने की भावना और निराशा पैदा होती है। जीवनसाथी के अलावा घर के कई सदस्यों के साथ रहना दुर्व्यवहार, विशेष रूप से वित्तीय दुर्व्यवहार के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है। अधिकांश वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध आवास उनकी आवश्यकताओं के लिए अनुपयुक्त और अनुपयुक्त पाया जा सकता है।

उन्हें जीवन भर लिंग आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उम्र बढ़ने की लिंग आधारित प्रकृति ऐसी है कि सार्वभौमिक रूप से, महिलाएँ पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं। 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु में, विधवापन महिलाओं की स्थिति पर हावी हो जाता है, 71 प्रतिशत महिलाओं और केवल 29 प्रतिशत पुरुषों ने अपने जीवनसाथी को खो दिया है। सामाजिक रीति-रिवाज महिलाओं को दोबारा शादी करने से रोकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के अकेले रहने की संभावना बढ़ जाती है। विधवा का जीवन कठोर नैतिक संहिताओं से भरा होता है, जिसमें अभिन्न अधिकारों का त्याग किया जाता है और स्वतंत्रता को दरकिनार किया जाता है। सामाजिक पूर्वाग्रह के परिणामस्वरूप अक्सर संसाधनों का अनुचित आवंटन, उपेक्षा, दुर्व्यवहार, शोषण, लिंग आधारित हिंसा, बुनियादी सेवाओं तक पहुँच की कमी और संपत्तियों के स्वामित्व को रोकना होता है। कम साक्षरता और जागरूकता के स्तर के कारण वृद्ध महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से बाहर रखे जाने की अधिक संभावना है

हड्डियों में कूट-कूट कर कैल्शियम भर देगा बादाम, बस नोट कर लीजिए इसे डाइट में शामिल करने के तरीके

क्या आप जानते हैं कि डेली डाइट में बादाम को शामिल करने से शरीर में कैल्शियम की कमी (Calcium Deficiency) को दूर किया जा सकता है? जी हां इस आर्टिकल में हम आपको बादाम खाने के कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप इस ड्राई फ्रूट के सभी फायदे (Benefits Of Eating Almonds) ले पाएंगे और शरीर में भी गजब की ताकत भर जाएगी। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि बादाम में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई और हेल्दी फैट्स जैसे कई पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं? ये पोषक तत्व आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने, हार्ट हेल्थ को बढ़ावा देने और आपकी त्वचा को चमकदार बनाने में खास भूमिका निभाते हैं।

इसके अलावा, बादाम में मौजूद कैल्शियम (Calcium) आपकी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। इसके साथ ही, यह मांसपेशियों के अच्छे कामकाज और नसों के संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करता है। अगर आप भी अपने शरीर में कैल्शियम का लेवल बढ़ाना चाहते हैं, तो बादाम को अपनी डाइट में शामिल करना एक बेहतरीन फैसला है। आइए जानते हैं कैसे आप बादाम को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिससे इसके ज्यादा से ज्यादा फायदे मिल सके।

क्यों हैं बादाम हड्डियों के लिए फायदेमंद?

कैल्शियम का खजानाः बादाम में कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है।

मैग्नीशियम का अच्छा सोर्सः मैग्नीशियम कैल्शियम को हड्डियों में अब्जॉर्ब होने में मदद करता है। ऐसे, में चूंकि बादाम में मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे डाइट का हिस्सा बनाने से कमजोर हड्डियों में जान भर सकती है।

विटामिन डीः बादाम में विटामिन डी की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन यह अन्य पोषक तत्वों के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है।

प्रोटीनः बादाम में प्रोटीन भी पाया जाता है जो हड्डियों के निर्माण और मरम्मत में जरूरी भूमिका निभाता है।

एंटीऑक्सीडेंट्सः बादाम में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो हड्डियों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं।

कैसे बनाएं बादाम को डाइट का हिस्सा

बादाम, सेहत के लिए काफी फायदेमंद ड्राई फ्रूट है, जो कैल्शियम का एक बेहतरीन सोर्स है। इसे आप कई तरीकों से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और शरीर में कैल्शियम की मात्रा को आसानी से बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।

सीधे खाएंः आप रोजाना मुट्ठी भर बादाम को नाश्ते या स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं।

दूध में मिलाकरः रात भर भिगोए हुए बादाम को छीलकर पीस लें और दूध में मिलाकर पीएं।

स्मूदी में मिलाएंः आप बादाम को अपनी स्मूदी में भी मिला सकते हैं।

सलाद में डालेंः आप कटे हुए बादाम को अपने सलाद में भी डाल सकते हैं।

दलिया में मिलाएंः आप बादाम को अपने दलिया में भी मिला सकते हैं।

बादाम का दूधः आप बादाम से दूध बनाकर भी पी सकते हैं।

बादाम का मक्खनः आप बादाम का मक्खन बनाकर ब्रेड या पनीर के साथ खा सकते हैं।

कितने बादाम खाने चाहिए?

आपको रोजाना 20 से 30 ग्राम बादाम खाना चाहिए, लेकिन अगर आपको सेहत से जुड़ी कोई समस्या है तो किसी डॉक्टर या डाइटीशियन से सलाह लेना जरूरी है।

कौन नहीं खा सकता बादाम?

कुछ लोगों को बादाम से एलर्जी होती है। अगर आपको बादाम से एलर्जी है तो आपको इनका सेवन नहीं करना चाहिए।

क्यों हर साल टूट जाते हैं न्यू ईयर रिजोल्यूशन? इन्हें हकीकत में बदलने के लिए काम आएंगे 5 टिप्स

दिव्यांशी भदौरिया

हर बार नए साल पर हम New Years Resolutions का मन बनाते हैं जैसे कि जिम जाना पढ़ाई करना या कोई खराब आदत छोड़ना! लेकिन कुछ दिन बाद हम फिर से पहले की तरह हो जाते हैं। ऐसे में इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है (why new years resolutions fail) और न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को टूटने से कैसे बचाया जा सकता है।

नई दिल्ली। नया साल, नई शुरुआत! यह कहावत आपने कई बार सुनी होगी। न्यू ईयर आने पर हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी भी थोड़ी और बेहतर हो जाए। यही वजह है कि हम सब खुद से नए-नए वादे करते हैं, जैसे कि कोई नई चीज सीखना या कोई बुरी आदत छोड़ना। हम सोचते हैं कि इस बार तो हम जरूर ये वादे पूरे करेंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये वादे क्यों टूट जाते हैं (Why New Year's Resolutions Fail)?

ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बस मन में सोच लेते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम ये कैसे करेंगे। अगर हम अपने वादों को पूरा करना चाहते हैं, तो हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। हमें ये सोचना होगा कि हम क्या करना चाहते हैं और फिर ये भी सोचना होगा कि हम ये कैसे करेंगे। हमें खुद को मजबूत बनाना होगा और एक प्लान पर काम करना होगा। आइए इस आर्टिकल में आपको न्यू ईयर रेजोल्यूशन के टूटने की वजहें और इन्हें हकीकत में बदलने के तरीके बताते हैं।

क्यों सच नहीं हो पाते न्यू ईयर रेजोल्यूशन?

जरूरत से ज्यादा उम्मीदें

न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते समय हम अक्सर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। हम एक साथ कई सारे टारगेट सेट कर लेते हैं, जैसे कि वजन कम करना, नई लैंग्वेज सीखना और करियर में आगे बढ़ना, लेकिन इतने सारे गोल्स को एक साथ पूरा करना बेहद मुश्किल होता है। जब हम अपनी एनर्जी को कई दिशाओं में बांटते हैं, तो हम किसी भी एक लक्ष्य पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते और आखिर में निराशा ही हाथ लगती है।

सब्र की कमी

अक्सर हम खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें रख लेते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी दिनचर्या में तुरंत बदलाव ला सकते हैं और कुछ ही समय में अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे, लेकिन असल में यह एक भ्रम है। आदतें बदलने में समय लगता है। धीरे-धीरे, लगातार कोशिशें करने से ही हम सफल हो सकते हैं। इसलिए, हमें छोटे-छोटे टारगेट सेट करने चाहिए और अपनी ग्रोथ पर ध्यान लगाना चाहिए।

प्लान की कमी

हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते समय यह नहीं सोचते कि हम अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे। हमारे पास कोई ठोस प्लान नहीं होता है और हम सिर्फ इरादे के भरोसे काम करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इच्छाशक्ति अकेले काफी नहीं होती है। हमें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी और उसका पालन भी करना होगा।

सोशल प्रेशर

अक्सर हम सोशल मीडिया या अपने आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होकरन्यू ईयर रेजोल्यूशंस सेट कर लेते हैं। हम दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकते हैं और ऐसे संकल्प ले लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते हैं। हमें दूसरों के बजाय खुद पर ध्यान लगाना चाहिए और ऐसे रेजोल्यूशन लेने चाहिए जो हमारे लिए असल में जरूरी हों।

सपोर्ट की कमी

जब हम कोई नया टारगेट रखते हैं, तो हमें अपने आसपास के लोगों का सपोर्ट मिलना भी जरूरी होता है। अगर हमें हमारे परिवार और दोस्तों का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो हमारे लिए अपने गोल्स को अचीव करना मुश्किल हो जाता है।

कमजोर इरादे

कई बार हम अपने रेजोल्यूशन को मानने में असफल इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे इरादे ही कमजोर होते हैं। जब हमें कोई मुश्किल आती है, तो हम आसानी से हार मान लेते हैं और यह भी यह वजह है कि हर साल रेजोल्यूशन हकीकत में बदलने से रह जाते हैं।

नेगेटिव सोच

अगर हम लगातार यह सोचते रहेंगे कि हम अपने टारगेट को हासिल नहीं कर पाएंगे, तो हम सचमुच उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। हमें पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए और खुद पर भरोसा करना चाहिए, तभी जाकर न्यू ईयर रेजोल्यूशन हकीकत में भी बदल पाएंगे।

न्यू ईयर रेजोल्यूशन को सच करने के लिए क्या करें?

ऐसा लक्ष्य चुनें जो आपके लिए मुश्किल तो हो, लेकिन नामुमकिन नहीं।

कैसे आप अपना लक्ष्य पूरा करेंगे, ये पहले से सोच लें।

बड़े लक्ष्य को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट लें।

आप कर सकते हैं, ये हमेशा याद रखें।

अपने परिवार या दोस्तों से मदद मांगने में शर्म न करें।

अगर गलती हो जाए तो निराश न हों, फिर से कोशिश करें।

लॉन्ग ड्राइव पर जाने का है प्लान, पेट्रोल पंप जाने से पहले चेक करें तेल के दाम

तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल-डीजल के दाम जारी कर दिये हैं। इनकी कीमतों में मार्च के बाद से ज्यादा बदलाव नहीं आया है। चूंकि सभी शहरों में इनके दाम अलग होते हैं। ऐसे में गाड़ीचालक को हमेशा ताजा कीमत चेक करने के बाद ही तेल भरवाना चाहिए। अगर आप भी लॉन्ग-ड्राइव पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको एक बार लेटेस्ट रेट चेक कर लेना चाहिए।

नई दिल्ली। गाड़ीचालक तेल की कीमतों में कटौती का इंतजार कर रहे हैं। इस साल मार्च में तेल की दाम में कटौती हुई थी। लोकसभा चुनाव से पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 2-2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी। इसके बाद से सभी शहरों में इनके दाम स्थिर बने हुए थे। हालांकि, कई बार तेल की कीमतों में नरमी आने की उम्मीद थी। दरअसल, जब भी कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आती है तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती होने की आस रहती है।

आपको बता दें कि तेल कंपनियां गाड़ीचालकों को सलाह देती है कि वह हमेशा ताजा कीमत चेक करने के बाद ही तेल भरवाएं। वहीं, अगर वह एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तब दोनों शहर में तेल के दाम क्या है, यह जरूर चेक करें। आपको बता दें कि सभी शहरों में इनके दाम अलग होते हैं। अभी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में जीएसटी (GST) नहीं लगता है। इस पर राज्य सरकार वैट (VAT) लगाते हैं। वैट की दरें हर राज्य में अलग होती है। इस कारण से सभी शहरों में तेल के दाम भी अलग होते हैं।

गाड़ीचालक तेल कंपनियों के वेबसाइट और ऐप्स से ताजा कीमत चेक कर सकते हैं। तेल कंपनियां रोजाना सुबह 6 बजे फ्यूल प्राइस अपडेट करती है। यह सिलसिला साल 2017 से जारी है। आइए इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए जानते हैं कि महानगर और बाकी शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol- Diesel Price 22

December 2024) क्या है?

महानगरों में पेट्रोल-डीजल के दाम

दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है।

मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89.97 रुपये प्रति लीटर है।

कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.76 रुपये प्रति लीटर है।

चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.34 रुपये प्रति लीटर है।

अन्य बड़े शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम

नोएडाः पेट्रोल 94.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.96 रुपये प्रति लीटर

गुरुग्रामः पेट्रोल 95.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.05 रुपये प्रति लीटर

बेंगलुरुः पेट्रोल 102.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.94 रुपये प्रति लीटर

चंडीगढ़ः पेट्रोल 94.24 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.40 रुपये प्रति लीटर

हैदराबादः पेट्रोल 107.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.65 रुपये प्रति लीटर

जयपुरः पेट्रोल 104.88 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.36 रुपये प्रति लीटर

पटनाः पेट्रोल 105.18 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.04 रुपये प्रति लीटर

केजरीवाल ने दिल्ली को दी बड़ी खुशखबरी, मुख्यमंत्री महिला सम्मान राशि और संजीवनी योजना का सोमवार से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

सुषमा रानी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। सोमवार से 18 साल से अधिक उम्र की महिलाएं 2100 रुपए प्रतिमाह लेने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान राशि और 60 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्ग संजीवनी योजना के तहत निजी या सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज कराने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। अरविंद केजरीवाल, वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और दिल्ली की सीएम आतिशी ने रविवार को इन योजनाओं का उद्घाटन किया है। सोमवार को खुद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सीएम आतिशी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में जाकर लोगों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ₹आप₹ के कार्यकर्ता घर-घर जाकर दोनों योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को दिल्ली का वोटर होना अनिवार्य है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेसवार्ता कर कहा कि अभी पिछले दिनों हमने दो योजनाएं ऐलान की थीं। जिसमें एक महिला सम्मान योजना थी। हम जानते हैं कि हमारी माताएं-बहनें कितनी मेहनत करती हैं। अपना घर संभालती हैं। सुबह 4 बजे से रात को 10-11 बजे तक मेहनत करती हैं। बच्चे जो देश का भविष्य हैं, उनको अच्छे संस्कार देकर पालती हैं। उनमें से कई माताएं-बहने बाहर जाकर नौकरी भी करती हैं। उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने एलान किया था कि हम लोग 2100 रुपए हर महीने उनके अकाउंट में डलवाएंगे। ऐसी कई बेटियां हैं, जिनका 12वीं के बाद कॉलेज छूट जाता है। हमने 12वीं तक शिक्षा फ्री की है लेकिन पैसों की कमी के कारण उनका कॉलेज छूट जाता है। इस 2100 रुपए उनकी पढ़ाई पूरी होने में मदद मिलेगी। उन्हें आगे उच्च शिक्षा में भी मदद मिलेगी। जो गृहणियां हैं, उन्हें 2100 रुपए से अपने घर का खर्चा चलाने में मदद मिलेगी। क्योंकि केंद्र सरकार की नीतियों ने बहुत महंगाई कर दी है। कई महिलाएं के छोटे-छोटे शौक होते हैं। वह अपने लिए कभी-कभी अच्छा शूट या साड़ी भी ला सकती हैं।

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि हमने जब से इस योजना का ऐलान किया है तब से बहुत फोन आ रहे हैं। हमारे पास इतने सवाल आ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा। आज मैं ऐलान करना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन सोमवार से शुरू होगा। आपको कहीं लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अपना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। हम आपके घर आएंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के हर इलाके में हजारों टीम बनाई है। हमारी टीम आपके घर आएंगी और आपके घर में जितनी भी महिलाएं हैं, उन सभी का रजिस्ट्रेशन करके आपको एक रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया जाएगा। उस कार्ड को संभालकर रखना है। आपकी सहूलियत के लिए हम लोग घर-घर के अंदर टीम भेज रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने दूसरी संजीवनी योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत हमारे 60 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं, उन सभी बुजुर्गों के इलाज का खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी। चाहे सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में इलाज हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो। आज तक किसी सरकार ने मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया। मिडिल क्लास का कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं, जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स और जीएसटी देते हैं। देश के विकास और उन्नति में पूरी जिंदगी अपना सहयोग देते हैं। लेकिन जब वह 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, तो मैंने देखा है कि अच्छे-अच्छे परिवारों में भी उनकी औलाद उनका ख्याल नहीं रखती है। बुढ़ापे में सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि मैं बीमार

हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरा इलाज कौन कराएगा। मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आम आदमी पार्टी की सरकार आपका इलाज कराएगी। इस योजना का भी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसका रजिस्ट्रेशन भी सोमवार से शुरू होगा।

"आप" के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने एक्स पर कहा कि कल (सोमवार) से दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। केजरीवाल कवच कार्ड का लॉन्च हर मां, बहन और बेटी के आत्मसम्मान, बुजुर्गों की देखभाल और हर परिवार के सुरक्षित भविष्य की गारंटी है।हमारे वॉलंटियर्स घर-घर जाकर इन योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे, सभी कह रहे हैं - दिल्ली सरकार की विकास और सम्मान की प्रतिबद्धता ने हर दिल को जोड़ा है। अरविंद केजरीवाल की दूरदर्शी सोच और ईमानदार राजनीति ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दिल्ली सरकार हर नागरिक की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

इस संबंध में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अब पैसों की कमी के कारण किसी बेटी की उच्च शिक्षा अधूरी नहीं रहेगी और महंगाई के इस दौर में किसी बहन को खर्चों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी उनके साथ है। दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला को प्रतिमाह 2100 रुपए मिलेंगे। इस महत्वपूर्ण योजना के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कल (सोमवार) से शुरू हो रही है। हमारी बहनों और बेटियों को रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारी टीम आपके घर आकर इस योजना का रजिस्ट्रेशन करेगी।

महिला सम्मान राशि के लिए पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला लाभार्थी की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। वह दिल्ली की निवासी और वोटर होनी चाहिए। वर्तमान या पूर्व में स्थायी सरकारी कर्मचारी (केंद्र या राज्य सरकार या एमसीडी) नहीं होनी चाहिए। अगर कोई महिला एमपी, एमएलए, काउंसलर है या रह चुकी हैं, वो भी पात्र नहीं होंगी। अगर किसी महिला ने पिछले वित्तीय सत्र में इनकम टैक्स भरा है, वो पात्र नहीं होंगी। जो महिलाएं दिल्ली सरकार की कोई पेंशन स्कीम, जैसे ओल्ड ऐज पेंशन, विडो पेंशन, डिसएबिलिटी पेंशन का लाभ ले रही है, वो पात्र नहीं होंगी। इसके अलावा, 18 साल से ज्यादा की उम्र की हर महिला मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत पत्र होगी।

सांसद ने सरकार को याद दिलाया कि हवाई यात्रा सस्ती करने का वादा था, लेकिन बढ़ती कीमतों ने इसे आम जनता के लिए मुश्किल बना दिया है

सुषमा रानी

नई दिल्ली। 22 दिसंबर देश के सभी एयरपोर्ट्स पर महंगे खानपान का मुद्दा लंबे समय से यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। संसद के इसी शीतकालीन सत्र में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाते हुए एयरपोर्ट्स पर महंगे दामों पर मिलने वाले पानी, चाय और स्नैक्स की समस्या को उजागर किया था। उनके इस प्रयास का नतीजा यह हुआ कि अब केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए "उड़ान यात्री कैफे" शुरू करने की योजना बनाई है। इसकी शुरुआत कोलकाता एयरपोर्ट से की जाएगी, जहां सस्ती दरों पर खानपान उपलब्ध कराया जाएगा।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घोषणा की है कि "उड़ान यात्री कैफे" की शुरुआत कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से की जाएगी। हालांकि यह एक पायलट प्रोजेक्ट होगा, जिसे बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के अन्य हवाई अड्डों पर भी लागू किया जाएगा। इस कैफे में पानी की बोतल, चाय, कॉफी और स्नैक्स वाजिब दामों पर उपलब्ध होंगे, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।

सांसद राघव चड्ढा ने इस बात पर खुशी जाहिर करते हुए इसे एक सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा, "आखिरकार सरकार ने आम जनता की पुकार सुन ली। भले ही शुरुआत कोलकाता एयरपोर्ट से हुई है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इसे जल्द ही देश के बाकी एयरपोर्ट्स पर भी लागू किया जाएगा। जिसके

बाद हवाई यात्रा करने वाले हमारे देश के नागरिकों को एयरपोर्ट्स पर पानी, चाय या कॉफी के लिए 100-250 रुपये तक खर्च नहीं करने पड़ेंगे। यह आम यात्रियों के लिए असुविधाजनक है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यात्रियों को उचित कीमत पर बेहतर सुविधाएं मिलें।"

संसद में एयरपोर्ट्स पर महंगे खानपान का मुद्दा उठाते हुए सांसद राघव चड्ढा ने कहा था कि देश के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को अत्यधिक महंगे खानपान और खराब प्रबंधन के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ₹एयरपोर्ट्स पर पानी की बोतल 100 रुपये की मिल रही है। एक कप चाय के लिए भी 200-250 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। क्या सरकार एयरपोर्ट्स पर सस्ते और उचित मूल्य की कैंटीन शुरू नहीं कर सकती ?₹ उन्होंने कहा था कि हमारे एयरपोर्ट्स की हालत अब बस अड्डों से भी बदतर हो गई है। लंबी कतारें, भीड़भाड़ और अव्यवस्थित प्रबंधन के कारण यात्रियों को अपनी यात्रा की शुरुआत में ही निराशा होती है।

उन्होंने ने जब ससंद में आम आदमी की इस आवाज को पुरजोर से उठाया था, तो सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी इस पहल काफी सराहना की थी औऱ इसे आम जनता के दिल की आवाज बताया था। उनके भाषण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी सुर्खियां बटोरी थीं। यहां तक कि लद्दाख में चीन सीमा से सटे चुशुल के काउंसलर कोंचोक स्टेनजिन ने भी उनकी बात का समर्थन करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा था, ₹लद्दाखियों को महंगे टिकट को लेकर बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर सर्दियों के दौरान जब हम बाकी लोगों से कटे रहते हैं। हवाई संपर्क ही हमारा एकमात्र विकल्प है, फिर भी किफायती किराया एक दूर का सपना बना हुआ है।"

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर चर्चा करते हुए कहा था, "सरकार ने वादा किया था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में यात्रा करवाएंगे, लेकिन हो रहा है इसका उल्टा। आज हवाई चप्पल तो छोड़िए, बाटा के जूते पहनने वाला भी हवाई यात्रा का खर्चा नहीं उठा सकता।₹ उन्होंने कहा था, सिर्फ एक साल के भीतर हवाई यात्रा के किरायों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम जनता पर बोझ बढ़ा है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली से मुंबई और पटना जैसे सामान्य रूट्स पर टिकटों की कीमतें 10,000 से 14,500 रुपये तक पहुंच गई हैं। वहीं, उन्होंने मालदीव का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार एक तरफ को मालदीव की बजाय लक्षद्वीप को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रचारित कर रही है, लेकिन मालदीव का किराया 17 हजार रुपये है, तो वहीं लक्षद्वीप का किराया 25 हजार रुपये है।

दो दिवसीय कला प्रदर्शनी को देखने पहुंचे अरविंद केजरीवाल

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली के स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की ओर से आयोजित कला प्रदर्शनी 'लहर' को देखने पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल वहां कलाकृतियां देखकर बच्चों के मुरीद हो गए। चाणक्यपुरी के शंकर चिल्ड्रन ट्रस्ट सेंटर में आयोजित दो दिवसीय कला प्रदर्शनी के आखिरी दिन रविवार को अरविंद केजरीवाल ने दौरा कर बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियां देखी और बच्चों से बात कर उनके हुनर को जमकर सराहा। उन्होंने कहा कि जब बच्चों को सही माहौल और सुविधाएं मिलती हैं तो उनकी कला और आत्मविश्वास चमत्कार कर सकते हैं। 10 साल पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थीं। आज वहीं से बच्चे संगीत, नृत्य और कला के ज़रिए अपनी पहचान बना रहे हैं।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि जब बच्चों को सही माहौल और सुविधाएं मिलती हैं तो उनकी कला और आत्मविश्वास चमत्कार कर सकते हैं। 10 साल पहले सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थीं। आज वहीं से बच्चे संगीत, नृत्य और कला के ज़रिए अपनी पहचान बना रहे हैं।दिल्ली सरकार के स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस द्वारा आयोजित कला प्रदर्शनी 'लहर' में बच्चों की अद्भुत प्रतिभा को नज़दीक से देखा। ये बच्चे कल के भारत की चमकती तस्वीर हैं।

लहर-2024 कला प्रदर्शनी की थीम परत थी। इतिहास, स्मृति और समय के प्रवाह की परतों को आपस में जोड़ना, यह

भारतीय कलाओं के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं पर प्रकाश डालता है। यह छात्रों को अपने आस-पास की छिपी हुई परतों का पता लगाने और संगीत, दृश्य कला, फिल्म निर्माण, अभिनय और मीडिया अध्ययन के माध्यम से अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है।

छात्रों ने इन आर्ट्स का किया प्रदर्शन

x दृश्य कला प्रदर्शनः एक गैलरी जिसमें भारतीय परंपराओं से प्रेरित पेंटिंग्स, मूर्तियाँ, मिनिएचर कला और ब्लॉक प्रिंटिंग दिखाई गई।

x इंटरएक्टिव स्टॉल्स और लाइव आर्टः पारंपरिक भारतीय कला तकनीकों के साथ-साथ आधुनिक डिजिटल क्रिएशन्स का प्रदर्शन।

x प्रस्तुतियाँः भारतीय शास्त्रीय और पश्चिमी संगीत की लाइव प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में रंग भर दिया।

x मीडिया और फिल्म स्टॉल्सः छात्रों द्वारा बनाई गई फोटोग्राफी, सिनेमैटोग्राफी और शॉर्ट फिल्म्स ने उनकी कहानी कहने और तकनीकी कौशल को दिखाया।

x रोचक कार्यशालाएँ: विजिटर्स ने गतिविधियों में भाग लिया और इस साल के थीम को और गहराई से समझा।

लहर-2024 प्रदर्शनी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कला को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। 2021 में शुरू हुए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस स्कूल में कला और प्रदर्शन कला में, भारतीय और पश्चिमी संगीत, फिल्म निर्माण, अभिनय, चित्रकला, और मीडिया की पढ़ाई कराई जाती हैं। इन स्कूलों में छात्रों का चयन कड़ी प्रक्रिया से होता है और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से उन्हें अनुभव आधारित शिक्षा दी जाती है।

ये पहल दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य कला के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और करियर के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करना है। दो दिवसीय कला प्रदर्शनी में आए लोगों ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल के क्रांतिकारी बदलाव की जमकर सराहना की।

श्री राम जानकी विवाह ट्रस्ट नए श्री राम सत्संग भवन में दस कन्याओं के हाथ पीले किए

सुषमा रानी

रविवार सामूहिकता किसी भी उत्सव का उमंग बढ़ा देती है। ऐसे ही एक सामूहिक आयोजन में एक साथ 10 अभावग्रस्त कन्या के हाथ पीले किए गए। यह आयोजन श्री राम सत्संग भवन, पंचशील गार्डन, नवीन शाहदरा में *श्रीराम जानकी विवाह ट्रस्ट* की तरफ से किया गया। यह समिति 1995 से प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह का आयोजन करती आ रही है जिसकी शुरुआत *स्व. गोपाल कृष्ण अरोड़ा* ने की थी। अब उनकी बेटी आरती अरोड़ा इस विवाह समिति का कार्य संभाल रही हैं। अभी तक समिति 375 कन्यायों की शादी करवाई है।

समुदाय भवन 'के' ब्लॉक नवीन शाहदरा से 10 बारातों को बाजों के साथ सजे हुए द्वारों से धूम-धाम से लाया जाता है। दूल्हे घोड़ों पर मुकुट पहन कर चलते है उनके आगे-आगे राम-सीता, भरत-माण्डवी, लक्ष्मण- उर्मिला तथा शत्रुघ्न-श्रुतकीर्ति के स्वरूप सुसजिज्त रथ में चलते है। सभी बारातें श्रीराम सत्संग भवन पहुंची जहाँ इन जोड़ों ने परस्पर माल्यार्पण किया। फिर समधियों की मिलनी की गई। हर जोड़े को दिया जाने वाला गृहस्थ जीवन के लिए दिए जाने वाला सामान भी प्रदर्शित किया गया।

विशिष्ट अतिथि के तौर पर केंद्रीय परिवहन एवं वित्त राज्य मंत्री *हर्ष मल्होत्रा* तथा *महंत नवल किशोर* ने भी जोड़ों को आशीर्वाद दिया। केंदीय मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस सामूहिक आयोजन से अभावग्रस्त परिवार को अपनी बेटी या बहन को वर्षों से सहयोग मिल रहा है।

सहयोगी सदस्य : अरूण बंसल, अनुपम भटनागर, कैलाश जैन, रमेश गुप्ता, वीना महतो, राकेश अरोड़ा, कुसुम वशिष्ठ, पूनम भटनागर, रमा अरोड़ा, रघुराज।

नमस्कार,

आज मैं आप सबके सामने एक नई शुरुआत के लिए खड़ा हूं। मैंने 2015 से 2020 तक मुंडका विधानसभा के विधायक के रूप में जनसेवा का काम किया। उस दौरान मैंने हरसंभव कोशिश की कि मेरे क्षेत्र के लोगों को उनके अधिकार मिलें और उनकी समस्याओं का समाधान हो।

मैंने आम आदमी पार्टी में यह सोचकर कदम रखा था कि यह पार्टी अन्ना हज़ारे जी के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की राह पर काम करेगी। लेकिन मेरे अनुभव ने मुझे कुछ और ही सिखाया। मैंने देखा कि इस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जनता की उम्मीदों को धोखा दिया है। शराब नीति और शीश महल जैसे मामलों में घोर भ्रष्टाचार हुआ। यहां तक कि महिलाओं का भी सम्मान नहीं किया गया, जैसा कि स्वाति मालीवाल जी के मामले में सामने आया।

दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में आज भी सड़कों की हालत बदतर है, प्रदूषण अपने चरम पर है, और कॉलोनियों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया है। मैंने मुख्यमंत्री से मिलने की 50 से ज्यादा बार कोशिश की, लेकिन मुझे हमेशा उनके निजी सहायकों द्वारा रोका गया। ये वही लोग हैं जो कभी बेरोजगार थे, और आज करोड़पति बन गए हैं।

मेरा विश्वास है कि राजनीति सेवा का माध्यम है, न कि संपत्ति बनाने का। मैंने अपने कार्यकाल में दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल का प्रस्ताव पास कराया, जो स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी का सपना था। लेकिन इस पार्टी ने उस सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम भी नहीं बढ़ाया।

आज मैं पूरी ईमानदारी से यह कहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने जनता को गुमराह किया है। मैं इस मंच से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को चुनौती देता हूं कि वे दिल्ली और मुंडका के विकास पर मुझसे बहस करें।

अब मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, वीरेंद्र सचदेव जी और आशीष सूद जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने देश और दिल्ली के विकास के लिए एक मजबूत विजन और ठोस योजनाएं बनाई हैं।

मेरा वादा है कि मैं अपने क्षेत्र और दिल्ली के विकास के लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा। राजनीति मेरे लिए जनसेवा है, और मैं इसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा।

जय हिंद, जय भारत।

दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लगते ही फ्लाइंग स्क्वायड हो जाएगा सक्रिय, अलग-अलग लोकेशन पर लगेंगे तीन-तीन नाके

दिल्ली विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही पश्चिमी जिले में तैयारियां जोरों पर हैं। आचार संहिता लागू होने से पहले सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतदान निष्पक्ष हो और अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें इसके लिए जिला निर्वाचन विभाग प्रतिबद्ध है। आचार संहिता लगते ही अलग-अलग जगहों पर नाके लग जाएंगे।

दिल्ली। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस दौरान निर्वाचन विभाग का कड़ा पहरा हर जगह नजर आएगा। पश्चिमी जिला निर्वाचन विभाग के अंतर्गत आने वाले सात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की बात करें तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में निगरानी के लिए अलग अलग लोकेशन पर तीन-तीन नाके लगाए जाएंगे।

इन नाकों पर संदिग्ध नजर आने वाले वाहनों की तलाशी, वाहन पर सवार लोगों से पूछताछ का दायित्व रहेगा। इसके अलावा तीन तीन फ्लाइंग स्क्वायड की नियुक्ति प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों के लिए होगी। ये फ्लाइंग स्क्वायड विधानसभा क्षेत्र में हो रही तमाम गतिविधियों पर भ्रमण कर निगरानी में जुटे रहेंगे।

मतदाता सूची से जुड़ा काम जोरों पर

पश्चिमी जिला के अंतर्गत आने वाले सात निर्वाचन क्षेत्रों में करीब 13 लाख 24 हजार मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें करीब 6.24 लाख मतदाता महिलाएं हैं। अभी मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के चलते इसे अंतिम आंकड़ा नहीं माना जा सकता है। संभव है कि इस संख्या में अभी बढ़ोतरी हो या इसमें कमी हो।

पुनरीक्षण के तहत अभी फार्म छह (सूची में नाम जुड़वाना), सात (किसी पंजीकृत नाम पर आपत्ति दर्ज कराना) व आठ (परिवर्तित पते पर नाम पंजीकृत कराना) भरने का काम चल रहा है। जो फार्म जमा हो चुके हैं, उनकी सत्यता जांची जा रही है। मतदाता सूची को लेकर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसे देखते हुए यह कार्य काफी संवेदनशील हो गया।

फार्म सात में किए जा रहे दावे की हो रही पड़ताल

निर्वाचन विभाग फार्म सात के तहत आपत्ति से जुड़े तमाम दावों की सत्यता की पड़ताल में जुटा है। इस फार्म के माध्मय से कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दलों का कार्यकर्ता मतदाता सूची में किसी का नाम गलत तरीके से दर्ज करने को लेकर आपत्ति जता जा सकता है। 29 अक्टूबर से पांच दिसंबर के बीच पश्चिमी जिला निर्वाचन विभाग को करीब 12 हजार मतदाताओं को लेकर आपत्ति मिल चुकी है। इन आपत्तियों में करीब 4777 आपत्तियों को स्वीकार किया गया वहीं करीब 3225 आपत्तियों को अस्वीकार किया जा चुका है। करीब 3948 आपत्तियां अभी विचाराधीन हैं।

तीन स्तरीय पड़ताल के बाद ही लिया जाता है निर्णय

फार्म सात आवेदन के माध्यम से किए जा रहे दावों को लेकर जिला प्रशासन तीन स्तरीय पड़ताल करता है। पहले स्तर पर बीएलओ जांच करते हैं। इसके बाद बीएलओ सुपरवाइजर की जांच होती है और अंत में ईआरओ या एईआरओ के स्तर पर जांचं होती है। इस जांच बाद ही निर्णय होता है। जिन जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने हैं, उनकी एक सूची सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी दी जाती है ताकि वे भी अपने स्तर पर जांच कर लें।

पश्चिमी जिला निर्वाचन विभाग के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र

नांगलोई जाट
मोतीनगर
मादीपुर
राजौरी गार्डन
हरिनगर
तिलक नगर
जनकपुरी

85 से अधिक के मतदाता की सहूलियत का रखा जाएगा ध्यान

फिलहाल जिले में 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या करीब 14868 है। इस उम्र में कई बुजुर्ग घर से निकलकर मतदान केंद्र तक जाने में दिक्कत महसूस करते हैं। ऐसे बुजुर्ग के लिए घर से ही मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने की बात चल रही है। ऐसे बुजुर्गों से मिलने बीएलओ स्वयं जाएंगे और बुजुर्ग की अनुमति मिलने पर घर से ही उनके मतदान का प्रबंध किया जाएगा। जिले में थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 84 है।

अधिसूचना लगने के तत्काल बाद आचार संहिता लग जाएगी। इसके पूर्व की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतदान निष्पक्ष हो, अधिक से अधिक मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल करें, इसे लेकर हम लोग प्रतिबद्ध हैं। मतदाता जागरुकता के लिए स्वीप से जुड़े क्रियाकलाप की योजना भी तैयार की जा रही है। - डॉ. किन्नी सिंह, जिला निर्वाची पदाधिकारी, पश्चिमी जिला

अब यूपी के इस जिले में निकला कब्रिस्तान की बाउंड्री के पास शिवलिंग, 150 वर्ष पुराना होने का दावा; सफाई कर किया जलाभिषेक

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद जिले के मोदीनगर के आबिदपुर मानकी गांव में 150 साल पुराना शिवलिंग कब्रिस्तान की बाउंड्री में स्थित है। हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने शिवलिंग के लिए अलग रास्ता दिलाने की मांग की है। उनका कहना है कि देखरेख के अभाव में शिवलिंग गंदगी से अटा हुआ है। पदाधिकारियों ने शिवलिंग पर सफाई कर जलाभिषेक भी किया।

गाजियाबाद। मोदीनगर तहसील क्षेत्र के गांव आबिदपुर मानकी में हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने शिवलिंग के लिए अलग रास्ता दिलाने की मांग उठाई है। पदाधिकारियों का दावा है कि 150 वर्ष प्राचीन यह शिवलिंग कब्रिस्तान की बाउंड्री में पीर के निकट है। पदाधिकारियों ने रविवार को शिवलिंग पर सफाई कर जलाभिषेक भी किया। वहां मंत्रोच्चारण भी किया।

उन्होंने अपनी मांग को लेकर मोदीनगर थाने में शिकायत दी है। गांव आबिदपुर मानकी गांव में एक कब्रिस्तान है। हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों को सूचना मिली थी कि कब्रिस्तान में बाउंड्री के निकट शिवलिंग है। देखरेख के अभाव में शिवलिंग गंदगी से अटा है।

साफ-सफाई कर किया जलाभिषेक

इस पर हिंदू युवा वाहिनी के जिला महामंत्री नीरज शर्मा के नेतृत्व में पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए। पदाधिकारियों के मुताबिक, सूचना सटीक निकली। पीर के पास शिवलिंग था, जो मिट्टी व गंदगी के कारण ढका था। टीम ने वहां सफाई की और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। इसके बाद मोदीनगर थाने पहुंचे।

पुलिस से कहा कि शिवलिंग से लोगों की आस्था जुड़ी है। इसलिए शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए अलग से रास्ता दिलाया जाए। पदाधिकारियों ने सोमवार को तहसील में भी शिकायत पत्र देने की बात कही है।

प्रशासन ने क्या कहा

इस बारे में एसडीएम मोदीनगर डॉ. पूजा गुप्ता का कहना है कि प्रकरण अभी उनकी जानकारी में नहीं है। जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई कराई जाएगी। वहीं, एसीपी मोदीनगर ज्ञान प्रकाश राय का कहना है कि मामला प्रशासन से जुड़ा है।

युवक और उसकी मंगेतर को मिल रही जान से मारने की धमकी

वहीं, मुरादनगर थाना क्षेत्र के कन्नौजा गांव में रहने वाले युवक व उनकी मंगेतर को जान से मारने की धमकी मिल रही है। बीते कुछ दिनों से अज्ञात लोग फोन पर गालीगलौज कर कर रहे हैं। विवाह से कुछ दिन पूर्व धमकी मिलने के कारण दोनों पक्ष तनाव से ग्रस्त हैं। कन्नौजा गांव में युवक अनुज कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं।

अनुज के स्वजन ने दो माह पूर्व उनका रिश्ता गाजियाबाद के लाल कुआ क्षेत्र की रहने वाली युवती के साथ किया था। युवक के अनुसार बीते कुछ दिनों से एक अज्ञात व्यक्ति उन्हें व उनकी मंगेतर को फोन करके रिश्ता तोड़ने के लिए दबाव बना रहा है। रिश्ता न तोड़ने पर आरोपी दोनों को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है।

फरवरी में दोनों की शादी होनी है, जिसकी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। धमकी के चलते दोनों पक्ष के लोग अनहोनी की आशंका से ग्रस्त हैं। युवक के पिता ने इस संबंध में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

किराएदार ने बुजुर्ग महिला को घर से निकाला, फर्जी दस्तावेजों से कब्जा करने का आरोप

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद में एक बुजुर्ग महिला ने अपने किराएदार पर मकान पर कब्जा करने और फर्जी दस्तावेज के जरिए घर हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि किरायेदार ने उनके बेटे के नाम से 35 लाख रुपये में मकान का सौदा कर कोर्ट में वाद दायर कर दिया। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

गाजियाबाद। संजय नगर में बुजुर्ग महिला ने अपने किरायेदार पर मकान पर कब्जा करने और फर्जी अनुबंध पत्र तैयार करने का केस दर्ज कराया है। पीड़िता का कहना है कि किरायेदार ने उनके बेटे के नाम से 35 लाख रुपये में मकान का सौदा कर कोर्ट में वाद दायर कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर मधुबन बापूधाम थाने में आरोपितों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

संजय नगर जी ब्लाक निवासी परबीन बेगम ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उनके यहां किरायेदार अमित चौधरी को रखा हुआ है। अमित चौधरी अपनी पत्नी मोनिका चौधरी और बेटे प्रिंस व रोहन के साथ रहते हैं। पीड़िता का आरोप है कि कुछ माह किराया देने के बाद अमित चौधरी ने किराया देना बंद कर दिया। उन्होंने मकान खाली करने को कहा तब किरायेदार ने मकान भी खाली करने से मना कर दिया।

बीमार बेटे के पास रहने फरीदाबाद चली गई महिला

उन्होंने सितंबर 2022 में पुलिस को शिकायत देकर आरोपित पर केस दर्ज कराया। पुलिस की मौजूदगी में किरायेदार ने बकाया किराया 10 लाख 90 हजार रुपये देने ओर 10 दिन में मकान खाली करने का आश्वासन दिया। इसी बीच महिला अपने बीमार बेटे के पास रहने फरीदाबाद चली गईं। जब लौटकर आईं तब उन्हें आरोपितों ने घर में घुसने नहीं दिया।

उनके बेटे के नाम से फर्जी एग्रीमेंट तैयार कराया

पीड़िता पुलिस के पास गईं तो उन्हें पुलिसकर्मियों ने बताया कि उनका मामला कोर्ट में चल रहा है। पीड़िता को कोर्ट से जानकारी मिली कि आरोपित ने उनके बेटे के नाम से फर्जी एग्रीमेंट तैयार कराया है जिसमें 35 लाख रुपये में मकान का सौदा किया है। किराये के रूप में दी गई धनराशि को किस्त के रूप में दिखाया है। इस अनुबंध पत्र के सहारे कोर्ट में वाद दायर किया है।

पीड़िता का कहना है कि उनके पति ने मकान खरीदा था। उनके पति की मृत्यु के बाद मकान जीडीए में वर्ष 2014 में उनके एवं उनके तीन बेटों एवं दो बेटी के नाम पर दर्ज है।

मोबाइल टावरों से सामान चोरी करने वाले पांच गिरफ्तार, सात करोड़ का माल बरामद

गाजियाबाद में मोबाइल टावरों से सामान चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने सामान चोरी करने वाले गिरोह के पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपितों से 74 आरआर यूनिट समेत करीब सात करोड़ रुपयों का माल बरामद किया है। आरोपित मोबाइल टावरों से चोरी किये गए माल को हांगकांग भेजते थे।

गाजियाबाद। क्राइम ब्रांच में मोबाइल टावरों से आरआर यूनिट समेत अन्य सामान चोरी करने वाले गिरोह के पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों से 74 आरआर यूनिट समेत करीब सात करोड़ रुपयों का माल बरामद किया है। आरोपित चोरी किये गए माल को हांगकांग भेजते थे।

पहले जावेद मीरापुरिया के साथ काम करता था शाहरुख : पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपित दिल्ली के कांति नगर निवासी शाहरुख मलिक, अनस खान, मेरठ के लिसाली गेट निवासी वसीम मलिक, हिंडन विहार निवासी साहिल मलिक और कयूम अंसारी हैं। पूछताछ में आरोपित शाहरुख ने बताया कि वह पहले जावेद मीरापुरिया के साथ काम करता था, लेकिन बाद में उसने अपना गिरोह अलग बना लिया।

पूरी डीलिंग करता है शाहरुख का चचेरा भाई : पुलिस ने आरोपितों से 74 आरआर यूनिट समेत 122 मोबाइल टावर बेसबैंड यूनिट, एक थार गाड़ी, एक स्विफ्ट और एक फ्रांक्स कार बरामद किया है। आरोपित शाहरुख का चचेरा भाई फईम हांगकांग में रहकर पूरी डीलिंग करता है। पुलिस आरआर यूनिट चोरी करने वाले गिरोह के 39 बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। जिनमें अंतरराष्ट्रीय तस्कर जावेद

एक महीने में डायल-112 पर एक ही नंबर से गईं 746 कॉल, जब पता चली हकीकत तो पुलिस रह गई दंग

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद में एक शख्स ने नवंबर 2024 में डायल 112 पर 746 बार झूठी कॉल की। उसने खुद को विपरीत परिस्थितियों में फंसा होने की झूठी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन कुछ नहीं मिला। बाद में नंबर भी बंद हो गया। मामले में डायल-112 के निरीक्षक की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी की तलाश में जुटी है।

गाजियाबाद। निवाड़ी में सिरफिरे ने नवंबर 2024 महीने में डायल 112 पर 746 बार कॉल की। खुद को विपरीत परिस्थितियों में फंसा होने की झूठी सूचना दी। 155 बार इवेंट आईडी जारी हुई। पीआरवी (पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल) मौके पर पहुंची। इसके बाद वापस लौट गई। मामले में डायल-112 के निरीक्षक की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस छानबीन में जुटी है।

आपातकालीन परिस्थिति में फंसने पर राहत के लिए शासन की तरफ से डायल 112 हेल्पलाइन जारी की गई है। इस पर तत्काल पुलिस सहायता मिलती है। कॉल करने पर मुख्यालय से तत्काल संबंधित पीआरवी को मौके पर भेजा जाता है।

नंबर भी हो गया बंद

नवंबर महीने में एक ही नंबर से डायल 112 पर 746 बार कॉल की। हर बार खुद को गंभीर स्थिति में फंसा होना बताया। इस पर पीआरवी मौके पर गई, लेकिन मौके पर कुछ नहीं मिला। बाद में नंबर भी बंद हो गया।

झूठी सूचना देकर बार-बार पुलिस को बुलाया

इसी तरह बार-बार झूठी सूचना देकर पुलिस को मौके पर बुलाया गया। लगातार झूठी सूचनाएं मिलने पर पुलिस ने नंबर की कुंडली खंगाली, जिसमें पता चला कि आरोपी निवाड़ी का कुम्हैड़ा गांव का समीर है।

डायल 112 के प्रभारी निरीक्षक रवि बालियान की तरफ से निवाड़ी थाने में केस दर्ज कराया गया। एसीपी मोदीनगर ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि आरोपित की तलाश में पुलिस जुटी है। जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी।

युवक और उसकी मंगेतर को मिल रही जान से मारने की धमकी

वहीं, मुरादनगर थाना क्षेत्र के कन्नौजा गांव में रहने वाले युवक व उनकी मंगेतर को जान से मारने की धमकी मिल रही है। बीते कुछ दिनों से अज्ञात लोग फोन पर गालीगलौज कर कर रहे हैं। विवाह से कुछ दिन पूर्व धमकी मिलने के कारण दोनों पक्ष तनाव से ग्रस्त हैं। कन्नौजा गांव में युवक अनुज कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं।

अनुज के स्वजन ने दो माह पूर्व उनका रिश्ता गाजियाबाद के लाल कुआ क्षेत्र की रहने वाली युवती के साथ किया था। युवक के अनुसार बीते कुछ दिनों से एक अज्ञात व्यक्ति उन्हें व उनकी मंगेतर को फोन करके रिश्ता तोड़ने के लिए दबाव बना रहा है। रिश्ता न तोड़ने पर आरोपित दोनों को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है।

फरवरी में दोनों की शादी होनी है, जिसकी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। धमकी के चलते दोनों पक्ष के लोग अनहोनी की आशंका से ग्रस्त हैं। युवक के पिता ने इस संबंध में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

43 वर्षों बाद भारत की सफ़ल कुवैत यात्रा 21-22 दिसंबर 2024-भारत कुवैत रिश्ता सभ्यताओं, सागर व व्यापार व्यवहार क़े अतीत से जुड़ा है

कुवैत में लाखों भारतियों के बीच मिनी हिंदुस्तान का जलवा- मैत्रीपूर्ण संबंध की जड़ें ऐतिहासिक हैँ
मिशन कुवैत पर 43 वर्ष के बाद भारतीय पीएम का दौरा गेम चेंजर साबित होगा-
एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर भारत जिस तेज़ी के साथ विश्व पर नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है, परंतु अगर नेतृत्व का विस्तार यूएन से लेकर पूरी दुनियाँ तक विस्तारित है तो भारत शीघ्र विश्व गुरु बन जाए तो इसमें किसी को अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि विज़न 2047 के कारण भारत अपनी हर नीति को रणनीतिक तरीके से दूरगामी परिणामों को प्राप्त करने के लिए क्रियान्वयन कर रहा है जो रेखांकित करने वाली बात है। ज़हां एक ओर पीएम नें पूर्वोत्तर क्षेत्रों का अपने कार्यकाल में 65 से अधिक बार दौरा किया है वहीं दूसरी और पापुआ न्यू गिनी से लेकर कुवैत यात्रा तक ऐसे अनेक देश है जहां चार पांच दशकों से कोई भारतीय पीएम नहीं गया है वहां की यात्रा कर भारत क़े सामरिक रिश्तों और वहां रह रहे भारतीयों में भारत के प्रति अलख़ जगा रहे हैं जिसके दूरगामी परिणाम हमें आगे देखने को जरूर मिलेंगे जिसका सटीक उदाहरण माननीय पीएम की 21-22 दिसंबर 2024 कुवैत यात्रा रही जिसमें 10 लाख से अधिक भारतीयों ने पीएम की सभा में मिनी हिंदुस्तान का एक अहसास पैदा करा दिया जो रेखांकित करने वाली बात है। चूँकि मिशन कुवैत 43 वर्षों के बाद भारतीय पीएम का दौरा गेम चेंजर साबित होगा, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, 43 वर्षों के बाद भारत की कुवैत यात्रा 21-22 दिसंबर 2024 सफल रही, भारत कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं, सागर व व्यापार व्यापार व्यवहार क़े अतीत से जुड़ा हुआ है।

साथियों बात अगर हम पीएम के कुवैत दौरे को अति महत्वपूर्ण होने की करें तो, कुवैत वर्तमान में खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) की अध्यक्षता कर रहा है - जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान और कतर भी शामिल हैं, यह एकमात्र जीसीसी सदस्य देश है, जहां पीएम ने 2014 में पदभार संभालने के बाद से अब तक दौरा नहीं किया है ।कोविड महामारी के कारण 2022 में प्रस्तावित यात्रा स्थगित कर दी गई थी। खाड़ी देश भारत के लिए प्रमुख व्यापार और निवेश साझेदार हैं, और नई दिल्ली की इन देशों के साथ मजबूत ऊर्जा साझेदारी भी है। कुवैत भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है ।कुवैत, भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चातेल आपूर्तिकर्ता है, जो देश की ऊर्जाआवश्यकताओं को तीन प्रतिशत तक पूरा करता है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार वित्तीय वर्ष 2023- 24 में 10.47 अरब अमेरिकी डॉलर रहा ।भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, इस यात्रा से भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के बीच संबंधों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है ।भारत मुक्त व्यापार समझौते के लिए जीसीसी के साथ बातचीत कर रहा है, इस यात्रा से भारत-कुवैत संबंधों को और अधिक मजबूती मिलेगी ।यात्रा के दौरान, पीएम एक सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत भी की और एक श्रमिक शिविर का भी दौरा किया, वह कुवैत के अमीर के विशेष अतिथि के रूप में 26 वें अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में भी शामिल।

साथियों बात अगर हम 43 वर्षों के बाद भारत के पीएम क़े कुवैत दौरे की करें तो, 43 साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री ने कुवैत की धरती पर कदम रखा है, उनसे पहले साल 1981 में इंदिरा गांधी कुवैत गई थीं। पीएम का कुवैत में ग्रांड वेलकम किया गया, इस दौरान उन्होंने दो खास शख्स से मुलाकता की जिनका जिक्र पीएम ने अक्टूबर में अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में की थी, इनक नाम अब्दुल्ला अल-बैरन और अब्दुल लतीफ अल-नसेफ है, इन्होंने महाभारत और रामायण का अरबी भाषा में अनुवाद किया है। पीएम ने मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि वह इनसे मिलकर काफी खुश हैँ। पीएम ने शनिवार को यहां कुवैत के दो नागरिकों से मुलाकात की और भारत के महत्वपूर्ण ग्रंथों रामायण और महाभारत का अरबी भाषा में अनुवाद और प्रकाशन करने के उनके प्रयासों की सराहना की। पीएम ने दोनों ग्रंथों के अरबी संस्करणों की प्रतियों पर अपना ऑटोग्राफ भी दिया। पीएम कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा के निमंत्रण पर कुवैत यात्रा की है, यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्षों में इस खाड़ी देश की पहली यात्रा है ।पीएम ने कहा, भारत दुनियाँ के उन पहले देशों में से एक है, जिसने कुवैत की स्वतंत्रता के बाद उसे मान्यता दी थी। इसलिए जिस देश से, जिस समाज से इतनी सारी यादें जुड़ी हैं, वहां आना मेरे लिए बहुत यादगार है। मैं कुवैत के लोगों और यहां की सरकार का बहुत आभारी हूं। उन्होंने कहा कि भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है और व्यापार-कारोबार का है। भारत और कुवैत, अरब सागर के दो किनारों पर बसे हैं। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं, बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। हमारा वर्तमान ही नहीं, बल्कि हमारा अतीत भी हमें जोड़ता है। पीएम ने कहा, जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, तो कुवैत ने हिंदुस्तान को लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई दी। हिज हाईनेस द क्राउन प्रिंस ने खुद आगे आकर सबको तेजी से काम करने के लिए प्रेरित किया। मुझे संतोष है कि भारत ने भी कुवैत को वैक्सीन और मेडिकल टीम भेजकर इस संकट से लड़ने का साहस दिया। उन्होंने कहा कि भारत के स्टार्टअप, फिनटेक से हेल्थकेयर तक, स्मार्ट सिटीज से ग्रीन टेक्नोलॉजी तक कुवैत की हर जरूरत के लिए कटिंग एग्ज सॉल्यूशन बना सकते हैं। भारत का स्किल्ड यूथ, कुवैत की फ्यूचर जर्नी को भी नई स्ट्रेंथ दे सकता है। भारत में आज दुनिया की स्किल कैपिटल बनने का भी सामर्थ्य है ।इसलिए भारत, दुनिया की स्किल डिमांड को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है ।पीएम ने कहा, 'आज का भारत एक नए मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज दुनिया का नंबर वन फिनटेक इकोसिस्टम भारत में है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। भविष्य का भारत दुनिया के विकास का हब होगा, दुनिया का ग्रोथ इंजन होगा।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि 43 वर्षों बाद भारत की सफ़ल कुवैत यात्रा 21-22 दिसंबर 2024- भारत कुवैत रिश्ता सभ्यताओं, सागर व व्यापार व्यवहार क़े अतीत से जुड़ा है ।कुवैत में लाखों भारतियों के बीच मिनी हिंदुस्तान का जलवा- मैत्रीपूर्ण संबंध की जड़ें ऐतिहासिक हैँ ।मिशन कुवैत पर 43 वर्ष के बाद भारतीय पीएम का दौरा गेम चेंजर साबित होगा।

- :सौजन्य:-
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

हरित परिवहन क्रांति के मुहाने पर खड़ा है भारत, 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है ईवी मार्केट

परिवहन विशेष न्यूज

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री अजय टम्टा ने शुक्रवार, 20 दिसम्बर को कहा कि भारत हरित परिवहन क्रांति के मुहाने पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में साल 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपये का होने की क्षमता है। केंद्रीय राज्यमंत्री टम्टा भारत मंडपम में 21वें ईवी एक्सपो में खालसा ईवी की बैटरी चालित तिपहिया वाहनों की नई सीरीज पेश करने के मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, "भारत हरित परिवहन क्रांति के मुहाने पर खड़ा है। भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपये का होने की क्षमता है, जिससे पूरे ईवी इकोसिस्टम में पांच करोड़ नौकरियां पैदा होंगी।"

टम्टा ने कहा, "इलेक्ट्रिक वाहन सिर्फ परिवहन का एक साधन नहीं हैं, वे एक टिकाऊ और आत्मनिर्भर भविष्य के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।" उत्पादों की नवीनतम श्रृंखला पर टिप्पणी करते हुए खालसा ई-व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शिवम नारंग ने कहा, "हमारा ध्यान राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (एनईएमएमपी) के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका उद्देश्य देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा हासिल करना है।" खालसा ईवी ने अपने नवीनतम तिपहिया मॉडल एल5 का अनावरण किया, जिसका नाम 'लुका' है। यह 200 किलोमीटर की रेंज वाली हाई-स्पीड लिथियम-आयन बैटरी द्वारा संचालित है, जो भारत में अपनी श्रेणी में पहला है। यह मॉडल यात्री और माल ढुलाई, दोनों

इस साल भारत में लॉन्च हुईं लक्जरी कार
फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और एडवांस फीचर्स से रही लैस

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में साल 2024 में लग्जरी गाड़ियों के लिए काफी शानदार रहा। इस साल Audi Q7 Facelift सबसे सस्ती और सबसे महंगी Rolls Royce Cullinan Facelift लॉन्च हुई। इन गाड़ियों में हाई क्वालिटी पावरफुल इंजन और बेहतरीन फीचर्स देखने के लिए मिले। आइए जानते हैं कि साल 2024 इन दोनों के अलावा और कौन-सी लग्जरी कार लॉन्च हुई।

नई दिल्ली। साल 2024 में भारत में बहुत सी कार लॉन्च हुई, जिसमें बजट फ्रेंडली से लेकर लग्जरी कारें शामिल रही। इस देश में बिकने वाली सभी लग्जरी कारों में से लग्जरी SUV का सबसे बड़ा योगदान रहा है। साल 2024 में कई ब्रैंड्स ने अपनी गाड़ियों को अपडेट करने के साथ ही नई पेशकश भी है। आइए जानते हैं कि साल 2025 में कौन-सी लग्जरी गाड़ियां लॉन्च हुई।

1. Audi Q7 Facelift

कीमतः 88.66 लाख रुपये।

Audi Q7 के फेसलिफ्ट मॉडल के डिजाइन में हल्के बदलाव किए गए हैं। इसमें 3-लीटर टर्बोचार्ज्ड V6 पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 340 PS की पावर और 500 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें पैनोरामिक सनरूफ, चार-जोन एसी, 8 एयरबैग्स और ADAS जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं।

2. Kia EV9

कीमतः 1.30 करोड़ रुपये

किआ इंडिया ने इसे कार्निवल लिमोजीन के साथ लॉन्च किया था। EV9 एक हाई-एंड मॉडल है जिसमें 99.8 kWh बैटरी और ड्यूल इलेक्ट्रिक मोटर्स दिए गए हैं। इसमें लगा हुआ इंजन 384 PS की पावर और 700 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी बैटरी फुल चार्ज होने के बाद 561 किमी तक का रेंज देती है। इसमें कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।

3. Porsche Macan EV

कीमतः 1.22 करोड़ से लेकर 1.69 करोड़ रुपये तक।

यह Porsche की पहली इलेक्ट्रिक SUV है जिसे भारत में लॉन्च किया गया है। इसमें 100 kWh बैटरी और 800V आर्किटेक्चर दिया गया है। इसमें लगा हुआ मोटर 584 PS की पावर और 1,130 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें लगी हुई बैटरी चार्ज होने के बाद 590 किमी तक का रेंज देती है।

4. Maserati Grecale

कीमतः 1.31 करोड़ से लेकर 2.05 करोड़ रुपये तक।

Maserati का नया लग्जरी SUV Grecale, जो GT, Modena और Trofeo ट्रिम्स में भारत लाई गई है। इसके GT और Modena में 2-लीटर 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन और Trofeo में 3-लीटर V6 इंजन दिया गया है, जो 530 PS की पावर और 620 Nm का टॉर्क जनरेट करते हैं। इसके इंटीरियर को मॉडर्न और मिनिमलिस्ट लुक में डिजाइन किया गया है।

5. Rolls Royce Cullinan Facelift

कीमतः 10.50 करोड़ रुपये से शुरू

Rolls Royce Cullinan के फेसलिफ्ट को इस साल भारत में लॉन्च किया गया है। फेसलिफ्ट को नए डिजाइन और फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें 6.75-लीटर V12 पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 571 PS की पावर और 850 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। फेसलिफ्ट में नया इल्यूमिनेटेड ग्रिल, नई 23-इंच एलॉय व्हील्स, और नई अपहोल्स्ट्री दी गई है।

खरीदनी है सस्ती स्पोर्ट्स बाइक, इन 5 की कीमत 2 लाख रुपये से कम

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। अगर आप एक स्पोर्ट बाइक लेने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं और आपका बजट ज्यादा नहीं है, तो यह खबर आपके के लिए है। दरअसल, भारतीय मार्केट में कई ऐसी स्पोर्ट्स बाइक है जिनकी कीमत 2 लाख रुपये से कम है। यह बाइक कई बेहतरीन फीचर्स और स्टाइलिश डिजाइन के साथ आती है। इतना ही नहीं यह बाइक बेहतरीन परफॉर्मेंस भी देती है। आइए इन बाइक्स के बारे में जानते हैं।

5. Yamaha MT-15

कीमतः 1.73 लाख रुपये।

यामाहा MT15 में 155cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 18.4 PS की पावर और 14.1 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। यह बाइक शहर में 56.87 किमी प्रति लीटर और हाईवे पर 47.94 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज देती है।

क्यों चुनें:

दमदार और स्टाइलिश बाइक

बेहतरीन ब्रेकिंग सिस्टम और टायर

4. Yamaha R15 V4

कीमतः 1.87 लाख रुपये।

यामाहा R15 V4 में 155cc का लिक्विड कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 18.4 PS की पावर और 14.2 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। यह बाइक शहर में 55.20 किमी प्रति लीटर और हाईवे पर 60.65 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है।

क्यों चुनें:

स्टाइलिश डिजाइन और पावरफुल इंजन।

बेहतर सेफ्टी के लिए डुअल-चैनल ABS।

3. Hero Karizma XMR

कीमतः 1.79 लाख रुपये।

हीरो करिज्मा XMR सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, 210cc इंजन के साथ आती है। इसमें लगा हुआ इंजन 25.5 PS की पावर और 20.4 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। यह बाइक एक लीटर पेट्रोल में शहर में 41.38 किलोमीटर और हाईवे पर 36.7 किलोमीटर तक का माइलेज देती है।

क्यों चुनें:

दमदार इंजन और शानदार लुक्स

बेहतरीन फीचर्स और हाई-टेक तकनीकी

2. Bajaj Pulsar RS 200

कीमतः 1.74 लाख रुपये।

बजाज पल्सर RS200 में 99.5cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 24.5 PS की पावर और 18.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को छह-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। यह बाइक एक लीटर पेट्रोल में 35 किलोमीटर तक का माइलेज देती है।

क्यों चुनें:

बेहतरीन परफॉर्मेंस और आकर्षक डिजाइन।

हाई-टेक फीचर्स और अच्छी सेफ्टी मिलती है।

1. TVS Apache RTR 160

कीमतः 1.24 लाख से लेकर 1.39 लाख रुपये तक।

TVS Apache RTR 160 में 160cc का सिंगल-सिलेंडर टू-वाल्व एयर-कूल्ड इंजन लगाया गया है, जो 15.31 bhp की पावर और 13.9 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह बाइक शहर में 45.06 किमी प्रति लीटर और हाईवे पर 46.99 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज देती है।

क्यों चुनें:

बजट में बेहतरीन स्पोर्ट्स बाइक

राइड मोड और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे शानदार फीचर्स

Kia Syros के सभी वेरिएंट अलग-अलग इंजन से लैस, कई एडवांस फीचर्स भी शामिल

परिवहन विशेष न्यूज

किआ इंडिया ने 19 दिसंबर को अपनी Kia Syros को भारत में पेश किया है। इस सब-4 मीटर एसयूवी को 6 वेरिएंट में लाया गया है। जिसमें अगल-अलग फीचर्स दिए गए हैं। इसके साथ ही इनके सभी वेरिएंट में अलग-अलग इंजन ऑप्शन भी पेश किया गया है। आइए जानते हैं कि Kia Syros के सभी 6 वेरिएंट कौन-कौन से इंजन ऑप्शन पेश किया गया है।

नई दिल्ली। किआ इंडिया ने अपनी अपनी मोस्ट अवेटेड कार Kia Syros को भारतीय बाजार में पेश किया है। इसे 6 वेरिएंट में लाया गया है, जिसमें HTK, HTK (O), HTK+, HTX, HTX+ और HTX+ (O) शामिल हैं। इन सभी फीचर्स में कुछ न कुछ अलग फीचर्स दिए गए हैं, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हम यहां पर अब आपको इन वेरिएंट में कौन-से इंजन ऑप्शन मिलेंगे, इसके बारे में बता रहे हैं।

Kia Syros: इंजन ऑप्शन

किया साइरोस को दो इंजन ऑप्शन के साथ लाया गया है, जो 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन है। इसका 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल वाला इंजन 120 PS की पावर और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, 1.5-लीटर डीजल वाला इंजन 116 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इतना ही नहीं इसमें अलग-अलग ट्रांसमिशन भी दिया गया है। आइए इनके बारे में जानते हैं।

Kia Syros HTK

किआ साइरोस का HTK वेरिएंट इसका बेस मॉडल है। इसमें 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। इस वेरिएंट वाले इंजन को 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

Kia Syros HTK (O)

साइरोस के इस वेरिएंट में 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का टर्बो डीजल ऑप्शन दोनों ही दिया गया है। अपनी पसंद के अनुसार आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि, इस वेरिएंट में इंजन को 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है।

Kia Syros HTK + और HTX

किआ साइरोस के HTK + और HTX वेरिएंट में भी HTK (O) वेरिएंट की तरह ही 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर की टर्बो डीजल इंजन ऑप्शन दिया गया है। इन दोनों वेरिएंट में 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है। साथ ही पेट्रोल इंजन के लिए 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन दिया गया है।

Kia Syros HTX + और HTX+ (O)

कंपनी ने साइरोस के HTX + और HTX+ (O) के वेरिएंट में 1 लीटर का टर्बो इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन के ऑप्शन को पेश किया गया है। इसमें पेट्रोल इंजन के लिए 7 स्पीड DCT का ऑप्शन और डीजल इंजन के लिए 6 स्पीड AT गियरबॉक्स दिया गया है।

इस साल लॉन्च हुई ये सबसे दिलचस्प Bikes, 125cc से लेकर 1300cc तक शामिल

परिवहन विशेष न्यूज

2024साल 2024 में कई बेहतरीन बाइक्स लॉन्च हुई है जिसकी एक लंबी लिस्ट है। इस साल हर तरह के राइडर के लिए मोटरसाइकिल भारत में लॉन्च हुई है। चाहे वो कंप्यूटर बाइक हो या फिर क्रूजर मोटरसाइकिल। यह बाइक कई इंजन साइज स्टाइल और फीचर्स के साथ आई है। आइए जानते हैं कि साल 2024 में कौन-कौन सी बाइक लॉन्च हुई है।

नई दिल्ली। साल 2024 में भारतीय मोटरसाइकिल बाजार में कुछ नए और दिलचस्प मॉडल्स देखने के लिए मिले हैं। यह बाइक्स हर राइडर की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। चाहे आपको एक सस्ती और स्टाइलिश 125 cc बाइक चाहिए हो या फिर 650 cc क्रूजर मोटरसाइकिल। इस साल मोटरसाइकिलों की लिस्ट में हर किसी के लिए कुछ खास रहा है। आइए जानते हैं कि साल 2024 में लॉन्च हुई टॉप मोटरसाइकिल के बारे में।

1. Bajaj Pulsar N125

कीमतः 93,900 रुपये।

पल्सर N 125 को 124cc का एयर-कूल्ड इंजन के साथ नया डिजाइन दिया गया है। इसमें लगा हुआ इंजन 12 bhp की पावर और 11 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसमें डिजिटल डैश और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

2. Hero Xtreme 125R

कीमतः 1,04,000 रुपये

हीरो की Xtreme 125R में 125 cc का इंजन दिया गया है, जो 11.55 PS की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक के इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसकी शार्प स्टाइल और एगाइल हैंडलिंग इसे खास बनाती है।

3. Bajaj Freedom 125

कीमतः 80,000 रुपये।

Bajaj Freedom 125 दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल है। यह बाइक पेट्रोल और CNG दोनों पर चल सकती है। इसमें 125 सीसी, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 9.3 bhp की पावर और 9.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी के मुताबिक, CNG पर यह बाइक 102 किलोमीटर प्रति किलोग्राम और पेट्रोल पर 65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। यानी, दोनों टैंकों पर यह बाइक लगभग 330 किलोमीटर की संयुक्त रेंज देती है।

4. Jawa 42 FJ

कीमतः 1.99 लाख से लेकर 2.20 लाख रुपये तक।

जावा 42 FJ में 334 cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 29.2 PS की पावर और 29.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच दिया गया है।

5. Bajaj Pulsar NS400Z

कीमतः 1.85 लाख रुपये।

पल्सर NS400Z में 73cc सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 40 PS की पावर और 35 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसमें USD फोर्क्स, ड्यूल-चैनल ABS और एलसीडी इंस्ट्रूमेंट कंसोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

6. Royal Enfield Guerrilla 450

कीमतः 2.39 लाख से लेकर 2.54 लाख रुपये तक।

Royal Enfield Guerrilla 450 में 452 cc लिक्विड-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 40.02 PS की पावर और 40 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसका इंजन तेज है और राइडिंग पोस्टर ADV बाइक से कहीं ज्यादा एंगेजिंग है।

8. BSA Gold Star 650

कीमतः 2.99 लाख से लेकर 3.35 लाख रुपये तक।

SA Gold Star 650 एक रेट्रो-स्टाइल, 650 cc सिंगल-सिलेंडर बाइक है, जो 45.6 PS की पावर और 55 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक के जरिए BSA ने भारत में दोबारा एंट्री मारी है। यह बाइक खास उन राइडर्स के लिए है, जो क्लासिक बाइक को पसंद करते हैं।

8. BMW R 1300 GS

कीमतः 20.95 लाख रुपये।

BMW R 1300 GS में 1300 cc, लिक्विड-कूल्ड, फ्लैट-ट्विन इंजन लगाया गया है, जो 145 PS की पावर और 149 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच के साथ जोड़ा गया है। इस बाइक का इलेक्ट्रॉनिक सूट बेहतरीन है और

कीटनाशकों से विषाक्त होती मिट्टी

विजय गर्ग

समय आ गया है कि पंजाब अपने कृषि क्षेत्र के कटु यथार्थ का सामना करे जो एक भयानक विभीषिका बन गया है। भटिंडा, मानसा और लुधियाना जिलों में खेतों की मिट्टी के 60 प्रतितशत नमूनों में जहरीले कीटनाशकों के अंश बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। इनमें घातक रसायन इंडोसल्फान व कार्बोफ्यूरान शामिल हैं और इनका स्तर किसी प्रकार सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है। यह केवल चेतावनी न होकर पूरी तरह से सामने आया गंभीर संकट तथा टिक-टिक करता टाइम बम है।

कीटनाशकों और उर्वरकों के इस गैरजिम्मेदार प्रयोग से पंजाब के खेत बंजर हो रहे हैं। 5 दिसंबर को 'विश्व मृदा दिवस' पर हमें तेजी से विघटित होती कृषि व्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दुनिया 'मृदा की देखभालः उपाय, निगरानी एवं प्रबंधन' की बात कर रही है। ऐसे में पंजाब में पागलपन खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है। एक समय उर्वर भूमि तेजी से बंजर जमीन में बदल रही है और यह केवल शुरुआत है। जहरीले रसायन केवल मृदा में ही नहीं रहते हैं, बल्कि वे हमारी खाद्य श्रृंखला में शामिल हो जाते हैं तथा खाने के हर कौर के साथ धीरे-धीरे हमारे भीतर जहर भरते हैं। यह प्रक्रिया यहीं नहीं थमती है, बल्कि जहरीले रसायनों के अवशेष हमारे डीएनए में प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार हमारे बच्चों तथा उनके भी बच्चों के लिए जेनेटिक परिवर्तन की जहरीली श्रृंखला पीछे छोड़ते हैं। ऐसे में हम ऐसे भविष्य का सामना कर रहे हैं जहां स्वास्थ्य पर खतरों और जेनेटिक विघटन की आशंका मौजूद है।

यह भयानक विभीषिका अनेक पीढ़ियों तक जा सकती है। हम न केवल वर्तमान पीढ़ी का स्वास्थ्य नष्ट कर रहे हैं, बल्कि हम अपने बच्चों को भी अपनी मूर्खता और लालच के कारण बरबादी की ओर धकेल रहे हैं। भावी पीढ़ियों का भविष्य ही संकट में पड़ गया है और हमारी निष्क्रियता के हर क्षण के साथ अपरिवर्तनीय जेनेटिक परिवर्तनों का खतरा मंडरा रहा है। समय आ गया है कि हम जागें, यथार्थ से मुंह चुराना बंद करें तथा संकट का सीधे-सीधे सामना करें। ऐसा न होने पर भावी पीढ़ियों का जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। भारत ने कीटनाशकों पर नियामक ढांचे की स्थापना 1968 में की थी. पर यह दयनीय रूप से पुरानी पड़ गई है और आधुनिक चुनौतियों का सामना करने में पूर्णतः विफल है जिससे कृषि रसायनों के खतरनाक दुरुपयोग का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि, इस ढांचे में संशोधन के प्रयास 2008 से जारी हैं, पर किसानों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण की सुरक्षा में काफी कमियां हैं। 1968 के कीटनाशक कानून तथा 1971 के कीटनाशक नियमों में समग्र परिवर्तनों की आवश्यकता है ताकि वे कीटनाशकों के दुरुपयोग से पैदा बहुआयामी संकटों का सामना कर सकें।

कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2020 पीएनबी को पुराने पड़ चुके कानूनों का स्थान लेने के लिए लाया गया था, पर इसमें महत्वपूर्ण सरोकारों को संबोधित किया जाना चाहिए। इस विधेयक में कीटनाशक पंजीकरण व लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को रेखांकित किया गया है, पर इसमें इनके खतरनाक प्रभाव से किसानों को भी समुचित सुरक्षा दी जानी चाहिए। 'पेस्टीसाइड एक्शन नेटवर्क' पैन इंटरनेशनल के आंकड़ों से निराशाजनक तस्वीर सामने आती है।

दुनिया भर में कीटनाशक विषाक्तता की दुर्घटनाओं से हर साल लगभग 11,000 लोगों की मौत होती है जिसमें अकेले भारत में खतरनाक रूप से 6,000 लोग हताहत होते हैं। इन आंकड़ों से स्वाभाविक रूप से कीटनाशक प्रयोग व्यवहारों और सुरक्षा उपायों में व्यापक कमियां उजागर होती हैं। अक्सर किसानों तथा ग्रामीण समाज को रसायनों के प्रयोग का खामियाजा भुगतना पड़ता है। यह खासकर गहन कृषि वाले क्षेत्रों, जैसे पंजाब में बहुत गंभीर है। धान और गेंहू की खेती में कीटनाशक प्रयोग की दर खतरनाक रूप से बहुत ऊंची है। इसमें औसतन 77 किलो प्रति हेक्टर कीटनाशक प्रयोग होता है, जबकि राष्ट्रीय औसत 62 किलो प्रति हेक्टर है। कीटनाशक उपभोग में भारत में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद पंजाब का तीसरा स्थान है। केन्द्रीय स्वायल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट सीएसएसआरआई के एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में 6.74 मिलियन हेक्टर जमीन लवणीयता की शिकार है और कृषि रसायनों के प्रयोग से स्थिति और खराब होती है।

लगातार कीटनाशकों के प्रयोग से 'माइक्रोबियल बायोमास' घट कर 30-50 प्रतिशत रह जाता है जिससे मृदा की उर्वरता प्रभावित होती है तथा जमीन फसलों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने में विफल हो जाती है। ऐसे में आधुनिक कृषि के लिए कीटनाशकों पर कठोर नियंत्रण जरूरी है जिसमें कीटनाशक, फफूंदनाशक या खरपतवार नाशक शामिल हैं।

उनकी विषाक्त प्रकृति के कारण उनके पूरे जीवनचक्र पर ही कठोर नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है जिसमें उत्पादन से लेकर प्रयोग तक शामिल हैं। वर्तमान नियामक ढांचे में सामने आ रहे विषविज्ञान आंकड़ों के आधार पर पंजीकृत कीटनाशकों की समय-समय पर समीक्षा में अक्षमता दिखती है। इस लापरवाही के कारण आम जनता के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा होता है। यह खासकर ऐसे देश में और गंभीर हो जाता है जहां कीटनाशकों का ठीक से प्रयोग न करना बहुत व्यापक हो गया है। पिछले तीन दशकों में कीटनाशकों के बेलगाम प्रयोग पर नियंत्रण का प्रयास नहीं हुआ है। इनका प्रयोग बढ़ने का कारण अक्सर आक्रामक मार्केटिंग तथा अधिक फसल पैदा करने के लिए कीटनाशकों के अधिकाधिक प्रयोग की रणनीति है।

वर्तमान समय में प्रशिक्षण प्रयास तेज करने की जरूरत है। 1994-95 से 2020-21 के बीच कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के प्लांट प्रोटेक्शन विभाग ने समन्वित कीटनाशक प्रबंधन-आईपीएम में केवल 585,000 किसानों को प्रशिक्षण दिया 150 मिलियन से अधिक किसानों वाले देश में बहुत कम है। कीटनाशक प्रबंधन के अंतरराष्ट्रीय कोड के अनुसार सरकारों तथा उद्योगों को किसानों तथा खुदरा विक्रेताओं को समग्र प्रशिक्षण एवं सूचनाओं से लैस करना चाहिए। इन संस्तुतियों का प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। अक्सर किसानों के संपर्क का एकमात्र साधन खुदरा विक्रेता होते हैं जो भ्रामक या आधी- अधूरी सूचनायें देते हैं। डेटा का उपयुक्त संग्रह न करना भी भारत में नियामक व्यवस्था के लिए समस्यायें खड़ी करता है।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो-एनसीआरबी दस्तावेजों के अनुसार कीटनाशकों के कारण होने वाली मौतें तभी पंजीकृत होती हैं जब उनको मेडिको लीगल मामलों के रूप में दर्ज किया जाए। इससे कीटनाशकों के गैर- संस्थागत हानिकारक प्रयोग तथा भयानक स्वास्थ्य दुष्प्रभावों के असंख्य मामले दर्ज नहीं हो पाते हैं। इसके कारण नीति निर्माण तथा जवाबदेही में बाधा पैदा होती है। भारत के कीटनाशक नियमन व्यवस्था में समुचित शिकायत निवारण व्यवस्था की कमी सामने आती है। किसानों तथा खेतिहर मजदूरों को कीटनाशकों के दुष्प्रभावों के मामले में न्याय व मुआवजा प्राप्त करने में भरी खर्च करना पड़ता है तथा इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है। इसके अलावा राज्य सरकारें खतरनाक कीटनाशकों पर केवल अस्थाई प्रतिबंध लगा सकती हैं जिसकी अवधि केवल 60 दिन होती है। इससे बहुत बड़ा समुदाय इसके जोखिमों का शिकार बनता रहता है। खेतिहर मजदूरों को कीटनाशकों के दुरुपयोग का ज्यादा जोखिम उठाना पड़ता है, जबकि उनको स्वास्थ्य जोखिम से निपटने के लिए सुरक्षा उपकरणों को खासकर गरम और नम माहौल वाले कृषि क्षेत्रों में जरूरी है। हालांकि, उपभोक्ता संरक्षण कानून सिद्धान्त रूप से किसानों पर भी लागू होता है, पर कीटनाशक निर्माताओं द्वारा भ्रामक लेबिलों या अधोमानक उत्पादों के प्रयोग के खिलाफ कानूनी लड़ाई आसान नहीं है। ऐसे में भारत को एक किसान- केन्द्रित कानूनी ढांचा तैयार करना चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो क्योंकि यही कृषि को सुरक्षित और टिकाऊ बनाने का एकमात्र रास्ता है। सरकार को खतरनाक कीटनाशकों पर तत्काल प्रतिंध लगा कर किसानों के स्वास्थ्य तथा उपभोक्ताओं की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक लागू करने चाहिए।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर

लोक से विमुख लोग

विजय गर्ग

हमारा भारतीय समाज लोकानुरागी रहा है। लोक उसकी आत्मा का हिस्सा रहा। लोक के आलोक में ही उसका जीवन दीप्त होता था। लेकिन धीरे- धीरे शहरीकरण ने लोक को हाशिये पर धकेल दिया है। इसका दुष्परिणाम समाज भोग रहा है। हम सब जानते हैं कि लोक का भोजन अमृत रहा है, क्योंकि उसमें शुद्धता की गारंटी हुआ करती थी। आज भी बहुत ह तक वहां शुद्धता बची हुई है। जबकि अनुभव यही बताता है कि शहरी भोजन अब जहर बनता जा रहा। सांसों में घुलता विषैला धुआं और खानपान में मिलावट शहरी जीवन का दुष्परिणाम हो गया है। लोक में रहने वाला समाज सहज रूप से शुद्ध प्रकृति के साथ रहता है।

चतुर्दिक पसरी हरियाली और नदी - तालाब की समृद्धि, तन-मन दोनों को स्वस्थ बनाए रखती। इधर कभी प्रकृति के संग रहने वाला नागर समाज अब धीरे-धीरे प्रकृति का दुश्मन होता जा रहा है। जबकि सभी जीव प्रकृति के साथ मजे से रहते हैं। तथाकथित विकास के नाम पर मनुष्य पेड़ काट रहा है। वह एक तरह से 'कालिदास' बना हुआ है। जिस डाल पर बैठा है, उसे ही काटे जा रहा। लोग नदी को प्रणाम तो करते हैं, पर तुरंत प्रदूषित भी करने लगते हैं। कुछ तो इतने चेतना - शून्य हो जाते हैं कि उनके कारखाने का दूषित जल सीधे जीवनदायिनी नदी समाता रहता है। तंत्र भी इसकी अनदेखी करता है। मनुष्य सुंदर विशाल पहाड़ों को खोद रहा है। उसके दुष्परिणाम भी भोग रहा। फिर भी वह सबक ग्रहण नहीं करता। पहले कहावत थी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है। अब गीदड़ की जगह मनुष्य शब्द का प्रयोग करना चाहिए। धीरे-धीरे अपने ही गांव से मनुष्य का मोह भंग हो रहा है। गांव में गाय पालने वाला व्यक्ति शहर आकर कुत्ते पालने लगता है। यह अजीब सा बदलाव है। गांव का आदमी शहर की ओर भाग रहा है और यहां कुचल कर मर रहा है, बीमार पड़ रहा है। गांव में रहते हुए जिस व्यक्ति के फेफड़े दुरुस्त थे, शहर में आकर वही फेफड़ा प्रदूषण का केंद्र बन गया है। पूरा शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है।

गनीमत है कि अभी भी गांव की बची-खुची आबादी शहरी व्यामोह में नहीं फंसी। आज भी सुदूर गांवों या वनप्रांतर में कुछ ऐसे लोग या समूह निवास कर रहे हैं, शहरी जीवन से कोई संपर्क ही नहीं रखना चाहते। वे सब अपनी दुनिया में मगन हैं, यानी प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे गांव से गंवईपन गायब होता जा रहा है, उसी तरह साहित्य से भी लोक-विमर्श धीरे-धीरे गायब होता जा रहा है। उसकी जगह महानगरीय जीवन और उसके संक्रमण केंद्र में आते जा रहे हैं। कहानी, कविताओं में, उपन्यासों में गांव की सोंधी खुशबू गायब है। अब जो नया साहित्य रचा जा रहा है, उसमें नग्नता की खुली वकालत है। नैतिकता अब चलन से बाहर मान ली गई है और आधुनिक होने की परिभाषा अलग मान ली गई है, जिसमें नैतिकता की जगह नहीं है। यह अजीब किस्म की उलटबांसी है। कुछ लोगों को लगता है कि यह देश 1947 में अस्तित्व में आया। उसका हजारों साल पुरानी परंपराओं से कोई वास्ता नहीं।

जैसे-जैसे हम लोक विमर्श या लोक जीवन से दूर होते जा रहे हैं, लोक ही क्या, अपने अतीत से ही हमारा विश्वास उठता जा रहा है। समाज में आत्महीनता या पतन आ रहा है और यह साहित्य में भी स्वाभाविक रूप से आ रहा है। हम प्रेमचंद की कहानियां पढ़ते हैं, तो उसमें लोक-विमर्श दिखाई देता है। परंपरा के प्रति लगाव भी नजर आता है। उनकी पूर्व संस्कार' जैसी कहानी की कहीं चर्चा नहीं होती। वेद व्यास जी का लोकप्रिय कथन है, 'प्रत्यक्षदर्शी लोकानाम सर्वदर्शी भवेन्नरः'। लोक जीवन को प्रत्यक्ष रूप से देखे बगैर हम मानव जीवन को ठीक से नहीं समझ सकते। इसलिए हमारे विमर्श के केंद्र में लोक- दर्शन होना चाहिए।

वर्ष 2025 से उम्मीदें

विजय गर्ग

इस समय अधिकांश लोग सोच रहे हैं कि आगामी वर्ष 2025 कैसा होगा ? ये अनुमान मिश्रित प्रकृति के हैं। प्रख्यात फ्रांसीसी संत और ज्योतिषी नास्टरडैमस ने 2025 में भारत और दुनिया के भविष्य के बारे में अनेक महत्वपूर्ण अनुमान लगाए थे। सोलहवीं शताब्दी के इस संत ने अनेक ऐसी घटनाओं का अनुमान लगाया था जिन्होंने दुनिया को स्वरूप दिया है। इनमें कोविड-19 वैश्विक महामारी से लेकर मनुष्य के चंद्रमा पर उतरने जैसी बातें शामिल हैं। इनसे नास्टरडैमस के अनुमानों पर आश्चर्य होता है। आज अनेक लोग सोलहवीं शताब्दी के इस संत की भविष्यवाणियों की व्याख्या कर रहे हैं और उनकी ऐतिहासिक सटीकता से प्रभावित हैं।

नास्टरडैमस ने अनुमान लगाया था कि रूस यूक्रेन युद्ध 2025 में समाप्त हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि दोनों देश जलवायु संकट और बाढ़ का सामना कर सकते हैं। 'द न्यूयार्क पोस्ट' अनुसार, तुर्किये और फ्रांस यूक्रेन और रूस के बीच शांति प्रक्रिया में काफी सहायता दे सकते हैं। नास्टरडैमस ने 2025 में इंग्लैंड में 'प्राचीन प्लेग' का पूर्वानुमान किया था जिससे एक ऐतिहासिक बीमारी के पुनः उभरने की आशंका पैदा होती है। इसके साथ ही उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध में ब्राजील की संलिप्तता तथा अनेक प्राकृतिक विभीषिकाओं का भी पूर्वानुमान लगाया है। इनके साथ ही नास्टरडैमस ने अनुमान लगाया है कि धरती की एक छुद्र ग्रह या एस्टीरॉयड से टक्कर हो सकती है। उन्होंने कहा था, 'ब्रह्मांड से आग का एक गोला उठेगा जो भविष्य बदलने वाला होगा।' नास्टरडैमस की भविष्यवाणियां हमें संभावित भावी घटनाओं तथा उनके प्रभावों के बारे में सचेत करती हैं।

जहां तक भारत के भविष्य का सवाल है, वर्ष 2025 की शुरुआत गणतंत्र दिवस परेड से होगी। इस बार परेड की थीम 'स्वर्णिम भारतः विकसित भारत' है, हालांकि अभी परेड में आमंत्रित मुख्य अतिथि के नाम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगला महाकुंभ 13 जनवरी, 2025 से 26 फरवरी, 2025 तक होगा महाकुंभ के अवसर पर हर 12 साल के अंतराल पर अलग-अलग स्थानों पर यह महान आध्यात्मिक आयोजन होता है। इस अवसर पर लाखों-लाख तीर्थयात्री और श्रृद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती पवित्र संगम पर स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकार महाकुंभ के इस आयोजन को असाधारण और अभूतपूर्व बनाने के सभी प्रयास कर रही हैं।

अगले वर्ष 2025 में भारत में तेज आर्थिक प्रगति, सामाजिक परिवर्तन तथा नई नई तकनीकें देखने को मिल सकती हैं। सरकार तकनीकी शिक्षा तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से सुधार कर रही है।

इन प्रयासों से आर्थिक प्रगति तेज होने की आशा है जो भारत में भावी समृद्धि के लिए शुभ संकेत है। विश्व स्तर पर भारत का महत्व इस वर्ष और बढ़ने की आशा है जिससे वह अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार, रक्षा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अपने प्रयास तेज करेगा। इनसे भारत की दुनिया भर में बढ़ती राजनीतिक शक्ति का भी पता चलता है। देश के स्तर पर विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है और इसकी एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। इस विपक्षी गठबंधन के भीतर पहले ही काफी तनाव पैदा हो गए हैं। तृणमूल कांग्रेस-टीएमसी तथा आम आदमी पार्टी आप ने गठबंधन से दूरी बना ली है। 'आप' ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने का मन बना लिया है। विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' में हालिया हरियाणा, महाराष्ट्र व झारखंड विधानसभा चुनावों के समय दरारें दिखने लगी थीं। जहां कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन किया, वहीं झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा- जेएमएम के साथ उसके गठबंधन ने चुनाव में विजय प्राप्त की। 'इंडिया' गठबंधन के सदस्य कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन से दुःखी हैं। उनकी नजर अब इस बात पर लगी है कि 2025 में होने वाले दिल्ली व बिहार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है। आगामी विधानसभा चुनावों से भावी राजनीतिक पुनः ध्रुवीकरण के भी संकेत मिलेंगे दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी में होंगे जहां भाजपा आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटाने के लिए कमर कस रही है। 'आप' ने निकट अतीत में अनेक चुनौतियों का सामना किया है जिसमें उसके अनेक नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं। एक रणनीति के रूप में 'आप' ने आतिशी को चुनावों तक दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। हालांकि, आप और कांग्रेस ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव एकसाथ लड़ा था। इसमें आप का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर था, पर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। अगले वर्ष बिहार विधानसभा के चुनाव भी होंगे। यह राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। यहां सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन- राजग का नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, पर उनको 'महागठबंधन' से कठोर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल राजद नेता तेजस्वी यादव कर रहे हैं। भाजपा और जनता दल युनाईटेड - जदयू राज्य में पुनः अपनी सरकार बनाने के लिए प्रयासरत हैं। वर्ष 2025 में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस अपनी शताब्दी मनाएंगे। आरएसएस अपनी स्थापना के 100 वर्ष सितंबर में पूरे करेगा, जबकि सीपीआई इस वर्ष दिसंबर में अपने शताब्दी समारोहों की शुरुआत करेगी। अनेक उतार-चढ़ावों के बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने भारतीय राजनीति और समाज को गहराई तक प्रभावित किया है। ऐसे में किसी सरकार के लिए अब भविष्य में उसे कमजोर करना बहुत कठिन हो गया है। इसके साथ ही दक्षिणपंथी दलों के ज्यादा लोकप्रिय होने के कारण कम्युनिस्ट पार्टियों का प्रभाव कम हो गया है।

अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर गौर करें तो भारत 2025 में क्वाड सम्मेलन आयोजित करेगा। मूलतः इसका आयोजन इस सितंबर में नई दिल्ली में होना था, पर इसमें भाग लेने वाले नेताओं के अन्य कार्यक्रमों के कारण इसका आयोजन न्यूयार्क में हुआ अब भारत 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिल्ली आने की आशा है। जिससे अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। अगले वर्ष के प्रारंभ में रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन की भारत यात्रा प्रस्तावित है जो एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। क्रेमलिन ने अगले वर्ष के प्रारंभ में इसकी तारीख तय करने की पुष्टि की है। यह यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन की पहली यात्रा होगी। कुल मिला कर वर्ष 2025 भारत के लिए उम्मीदों से भरा है।

अर्थव्यवस्था की अच्छी प्रगति हो रही है तथा विदेशी संबंध स्थिर हैं, हालांकि अभी राजनीतिक स्थिति अस्पष्ट है। अगले वर्ष देखना होगा कि कांग्रेस की स्थिति में कुछ सुधार होता है अथवा भाजपा व अन्य क्षेत्रीय पार्टियां मतदाताओं पर अपनी पकड़ और मजबूत करने में सफल होती हैं।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद

खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने की कुंजी

विजय गर्ग

जलवायु-स्मार्ट कृषि एक परिवर्तनकारी समाधान के रूप में उभरती है, जो उत्सर्जन को कम करने और खाद्य प्रणालियों को सुरक्षित करने की रणनीतियों के साथ स्थायी प्रथाओं का संयोजन करती है। आहार में बदलाव और बढ़ती वैश्विक आबादी के कारण भोजन की मांग लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में, लगभग 690 मिलियन लोग - या दुनिया की 8.9 प्रतिशत आबादी - भूख से पीड़ित हैं। 2050 तक, दुनिया को अनुमानित 9 अरब लोगों के भरण-पोषण के लिए लगभग 70 प्रतिशत अधिक भोजन का उत्पादन करने की आवश्यकता होगी, जो खाद्य सुरक्षा को एक गंभीर चुनौती बनाता है। जलवायु परिवर्तन इस समस्या को और बढ़ा देता है, जिससे खाद्य उत्पादन का पर्यावरणीय प्रभाव और भी तीव्र हो जाता है। कृषि, आवश्यक होते हुए भी, जलवायु संकट में एक प्रमुख योगदानकर्ता है, जो वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 19 प्रतिशत से 29 प्रतिशत के बीच उत्पन्न करती है। वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं से आर्थिक नुकसान भी बढ़ रहा है और कृषि क्षेत्र विशेष रूप से असुरक्षित है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनआईएसडीआर) के अनुसार, आपदा प्रभावित देशों को 1998 और 2017 के बीच 2,908 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान हुआ, जिसमें से 77 प्रतिशत नुकसान जलवायु संबंधी आपदाओं के कारण हुआ। हाल के वर्षों में, कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अधिक स्पष्ट हो गया है। उदाहरण के लिए, भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण 2010 और 2039 के बीच देश भर में प्रमुख फसल की पैदावार में 9 प्रतिशत तक की कमी का अनुभव होने का अनुमान है। क्षेत्रीय प्रभाव और भी गंभीर हो सकते हैं, चावल के लिए 35 प्रतिशत, गेहूं के लिए 20 प्रतिशत, ज्वार के लिए 50 प्रतिशत, जौ के लिए 13 प्रतिशत और मक्के के लिए 60 प्रतिशत तक की संभावित हानि हो सकती है। जलवायु परिवर्तन खाद्य उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जबकि पहले से ही नाजुक पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण में तेजी लाता है। इन चुनौतियों का मुकाबला करने

के लिए, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर (सीएसए) प्रथाओं को अपनाना जरूरी है, जिसका उद्देश्य उत्पादकता और आय में लगातार वृद्धि करते हुए कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है। सीएसए स्थायी कृषि प्रथाओं और ग्रामीण विकास लक्ष्यों को एकीकृत करता है, जो बेहतर पर्यावरण प्रबंधन और भूख में कमी जैसे व्यापक उद्देश्यों में योगदान देता है, जैसा कि सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) में उल्लिखित है। भारत में जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियाँ: कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए भारत सक्रिय रूप से जलवायु-स्मार्ट कृषि (सीएसए) प्रथाओं को अपना रहा है। इनमें पैदावार बढ़ाने और उत्सर्जन को कम करने के लिए जीरो-टिलेज जैसी संरक्षण कृषि तकनीकें, जैव विविधता और लचीलेपन को बढ़ाने के लिए कृषि वानिकी, और संसाधनों को अनुकूलित करने के लिए जीपीएस और जीआईएस जैसी सटीक कृषि तकनीकें शामिल हैं। ड्रिप सिंचाई जैसी जल प्रबंधन रणनीतियाँ दक्षता में सुधार करती हैं, जबकि कुशल पशुधन प्रबंधन राजस्व और उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाता है। सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा का तेजी से उपयोग किया जा रहा है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो गई है। फसल विविधीकरण, फलियों के साथ चक्रीकरण और जलवायु-लचीली किस्मों की खेती जैसी प्रथाएं स्थिरता को बढ़ाती हैं, जबकि एकीकृत कीट प्रबंधन और फसल अवशेष प्रबंधन रासायनिक उपयोग और प्रदूषण को कम करते हैं, जिससे दीर्घकालिक कृषि और पर्यावरणीय स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है। भारत में जलवायु-स्मार्ट कृषि के समक्ष चुनौतियाँः इसके असंख्य लाभों के बावजूद, भारत में सीएसए प्रथाओं को अपनाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तनशीलताः बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा और घटते जल संसाधनों से फसल उत्पादकता 10-40 तक कम होने का खतरा है।सदी के अंत तक प्रतिशत. समुद्र के बढ़ते स्तर, चक्रवात और तूफ़ान से कृषि भूमि खतरे में पड़ जाती है, खासकर सुंदरबन, केरल और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में। उच्च लागतः सीएसए विधियों को लागू करने में अक्सर महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश शामिल होता है, जो किसानों को रोक सकता है। नीति और नियामक बाधाएंः अपर्याप्त नीतियां और प्रतिबंधात्मक नियम व्यापक सीएसए अपनाने में बाधा डालते हैं। जलवायु-स्मार्ट कृषि को अपनाना अब वैकल्पिक नहीं बल्कि एक तत्काल आवश्यकता है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

राष्ट्रीय गणित दिवस 2024: अन्वेषण करें, सीखें और प्रेरित हों

विजय गर्ग

गणित दिवस, 22 दिसंबर को, भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाई जाती है। गणितज्ञों ने रामानुजन की प्रतिभा की तुलना 18वीं और 19वीं सदी के जैकोबी और यूलर जैसी हस्तियों से की है। संख्या सिद्धांत में उनके योगदान को विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, और उन्होंने विभाजन कार्य को आगे बढ़ाया। 2012 से, 22 दिसंबर को भारत के राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कई शैक्षणिक गतिविधियाँ होती हैं। 2017 में, आंध्र प्रदेश के चित्तूर में कुप्पम में रामानुजन मठ पार्क के उद्घाटन से इस दिन का महत्व बढ़ गया था। श्री रामानुजन और अन्य गणित प्रेमी दुनिया भर में पाए जाते हैं, और कुछ लोग इस विषय के बारे में और अधिक जानने में दूसरों की मदद भी करते हैं। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की उल्लेखनीय विरासत का सम्मान करते हुए, बड़े उत्साह के साथ राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 मनाया जा रहा है। दिन दिलचस्प गतिविधियों से भरा हुआ था, जिसमें दैनिक जीवन में गणित के महत्व पर जोर दिया गया था। इंटरैक्टिव सेमिनारों, अंकगणितीय क्विज़ और समस्या-समाधान अभ्यासों से छात्रों का उत्साह और संख्याओं के प्रति प्रेम बढ़ा। भविष्य को आकार देने में गणितीय अवधारणाओं के महत्व पर चर्चा करने के लिए अतिथि शिक्षकों द्वारा एक विशेष संगोष्ठी आयोजित की गई। राष्ट्रीय गणित दिवस का इतिहास भारत में गणित दिवस के संस्थापक प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन हैं, जिनके योगदान ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समाज को प्रभावित किया है। रामानुजन का जन्म 1887 में तमिलनाडु के इरोड में एक अयंगर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने स्वयं के कई प्रमेय विकसित किए और न्यूनतम औपचारिक शिक्षा के बावजूद बारह साल की उम्र में त्रिकोणमिति में पारंगत हो गए। 14 साल की उम्र में, रामानुजन अपना घर छोड़कर भाग गए और मद्रास के पचैयप्पा कॉलेज में दाखिला लिया। रामानुजन फ़ेलो ऑफ़ आर्ट्स की डिग्री के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करने में असमर्थ थे क्योंकि, अपने साथियों की तरह, वे अन्य विषयों में समान सफलता प्राप्त किए बिना केवल गणित में ही सफल हुए। अत्यधिक गरीबी के बावजूद रामानुजन ने गणित में स्वतंत्र शोध करने का निर्णय लिया। महत्वाकांक्षी गणितज्ञ ने तुरंत चेन्नई के गणित की ओर ध्यान आकर्षित किया। इंडियन मैथमैटिकल सोसाइटी के संस्थापक, रामास्वामी अय्यर ने उन्हें 1912 में मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्कशिप हासिल करने में मदद की। उसके बाद, रामानुजन ने अपना काम ब्रिटेन में गणितज्ञों को भेजना शुरू किया। कैम्ब्रिज के जीएच हार्डी नामक गणितज्ञ रामानुजन के प्रमेयों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें 1913 में लंदन आमंत्रित किया। 1914 में, रामानुजन ने ब्रिटेन की यात्रा की, जहाँ हार्डी ने उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज में दाखिला लेने में मदद की। 1917 में लंदन मैथमैटिकल सोसाइटी के सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद रामानुजन सफलता की राह पर थे। उन्हें 1918 में रॉयल सोसाइटी का फेलो भी बनाया गया, जिससे वह यह सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के लोगों में से एक बन गए। राष्ट्रीय गणित दिवस का महत्व आइए राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 के बारे में विस्तार से देखेंः राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 पर त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ें। रामानुजन ने त्रिकोणमिति प्रमेय स्वयं विकसित किए। यह अब तक के सर्वश्रेष्ठ गणितीय आविष्कारों में से एक है। 2024 में राष्ट्रीय गणित दिवस पर रामानुजन फिल्म देखने पर विचार करें। फिल्म में रामानुजन के जीवन को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। जैसा कि रामानुजन ने दिखाया है, प्रत्येक छात्र में अद्वितीय ताकत और कमियां होती हैं। हालाँकि अपना सर्वश्रेष्ठ करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है, ऐसे बच्चे की मदद करना और उसे प्रोत्साहित करना न भूलें जो असाधारण रूप से अच्छा करता हैविशेष विषय। राष्ट्रीय गणित दिवस उल्लेखनीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का सम्मान और जश्न मनाता है, जिन्होंने अन्य विषयों में संघर्ष करने के बाद अपने दम पर गणित का अध्ययन करने के लिए कॉलेज छोड़ दिया। गणित दिवस की समयरेखा 1887 (रामानुजन का जन्म हुआ): एक महान गणितज्ञ जिन्होंने अनुशासन पर अमिट प्रभाव डाला, रामानुजन का जन्म तमिलनाडु के इरोड में एक गरीब अयंगर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1918 (एक उच्च उपलब्धि): ब्रिटेन में लंदन मैथमैटिकल सोसाइटी में शामिल होने के लिए चुने जाने के तुरंत बाद, रामानुजन इतिहास में रॉयल सोसाइटी के फेलो नामित होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्तियों में से एक बन गए। 2012 (गणित दिवस को मान्यता दी गई): रामानुजन की उपलब्धियों के सम्मान में, पूर्व भारतीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने 22 दिसंबर, रामानुजन के जन्म के दिन, को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया। 2019 (द रॉयल सोसाइटी ऑनर्स रामानुजन): प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने साथी के सम्मान में एक विशेष संदेश ट्वीट किया। त्रिकोणमिति के बारे में 5 आश्चर्यजनक तथ्य मौलिक पहचान आठ त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ हैं जिन्हें मौलिक सर्वसमिकाएँ कहा जाता है, उनमें से तीन को पाइथागोरस सर्वसमिकाएँ कहा जाता है क्योंकि वे पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित हैं। एक प्राचीन गणना तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, खगोल विज्ञान अनुसंधान में ज्यामिति के उपयोग के परिणामस्वरूप त्रिकोणमिति का विकास हुआ। संगीत के रूप में गणित एक एकल नोट को साइन वक्र पर दर्शाया जा सकता है, एक तार को एक दूसरे के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने वाले कई साइन वक्रों के साथ दर्शाया जा सकता है, और ध्वनि तरंगें दोहराए जाने वाले तरंग पैटर्न में यात्रा करती हैं जिन्हें ग्राफिक रूप से साइन और कोसाइन कार्यों द्वारा दर्शाया जा सकता है। त्रिकोणमिति का संगीत से गहरा संबंध है और यह संगीत सिद्धांत और उत्पादन का एक प्रमुख घटक है। त्रिकोणमिति हमें नेविगेट करने में मदद करती है यदि 1700 के दशक में हमारे पास त्रिकोणमिति होती, तो संभवतः हम एक जहाज के नाविक होते। थोड़ी सी त्रिकोणमिति और एक अच्छी घड़ी के साथ, एक कुशल नाविक अटलांटिक महासागर के बीच में भी अपनी स्थिति का पता लगा सकता है।

सेविंग अकाउंट में इतने रुपये से ज्यादा का लेनदेन न करें, एक बार किया तो आज जाएंगे आयकर विभाग के नजर में

परिवहन विशेष न्यूज

अपनी सेविंग को बचाने के लिए हम सेविं अकाउंट की मदद करते हैं। सेविंग अकाउंट को लेकर भी कई नियम हैं। इन नियमों के बारे में कई लोग नहीं जानते हैं। अगर आप सेविंग अकाउंट से एक लिमिट से ज्यादा लेनदेन करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। हम आपको इस आर्टिकल में इन नियमों के बारे में बताएंगे।

नई दिल्ली। सेविंग अकाउंट में हम अपनी जमा-पूंजी रखत हैं। लेकिन, इसमें भी एक सीमा होती है। अगर इस सीमा से ज्यादा पैसा हमारे अकाउंट में होती है तो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नजर में आ सकते हैं। इस बात से कई लोग अभी तक अनजान हैं। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि सेविंग अकाउंट को लेकर आयकर विभाग का क्या नियम हैं।

इससे ज्यादा लेनदेन पर देनी होगी जानकारी

फाइनेंशियल एक्सपर्ट के अनुसार एक फाइनेंशियल ईयर में सेविंग अकाउंट में कुल जमा राशि 10 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वह इस सीमा से ज्यादा होती है तो फिर इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी पड़ेगी। वहीं, आयकर अधिनियम की धारा 269एसटी के अनुसार खाताधारक एक दिन में 2 लाख रुपये का लेनदेन कर सकता है। उससे ज्यादा के लेनदेन करने पर उसे बैंक को कारण बताना पड़ेगा।

बैंक भी देती हैं ये जानकारी

नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 50,000 रुपये या उससे ज्यादा राशि जमा करते हैं तो उसे इसकी जानकारी बैंक को देनी पड़ती है। इसके अलावा खाताधारक को अपने पैन की डिटेल्स भी देनी होती है। अगर खाताधारक के पास पैन नहीं होता है तो उसे फॉर्म 60 या 61 सबमिट करना होता है। वहीं, 10 लाख रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन को उच्च-मूल्य वाला लेनदेन माना जाता है। इस तरह के लेनदेन की जानकारी बैंक आयकर विभाग को देती है।

नोटिस आए तो क्या करें?

कई बार हम किसी वजह से इतनी बड़ी लेनदेन कर लेते हैं और आयकर विभाग को इसकी जानकारी नहीं देते हैं। ऐसे में हमारे पास विभाग द्वारा नोटिस आ जाता है। अब सवाल आता है कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अगर आपके पास इस तरह का कोई नोटिस आता है तो आपको इसका जवाब देना चाहिए। नोटिस के जवाब के साथ आपको उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स की भी जानकारी देनी चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स में स्टेटमेंट, निवेश रिकॉर्ड, या एसेट आदि शामिल होते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार अगर आपको नोटिस का जवाब देने या डॉक्यूमेंट को लेकर कोई

31 दिसंबर से पहलें करे टैक्स से जुड़ा ये काम, समय चूकने पर लगेगा जुर्माना

परिवहन विशेष न्यूज

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आयकर विभाग समयसीमा तय करती है। करदाता को इस समयसीमा के भीतर रिटर्न फाइल करना होता है। अगर वह डेडलाइन के अंदर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें लेट फीस देनी पड़ती है। हालांकि विभाग ने करदाता को बिलेटिड रिटर्न फाइल करने का मौका दिया है। अगर आपने भी जुलाई में आईटीआर फाइल नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए है।

नई दिल्ली। टैक्सपेयर को साल में एक बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने होते हैं। इसके लिए आयकर विभाग द्वारा एक समयसीमा तय की जाती है। अगर करदाता समयसीमा के भीतर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें पेनल्टी भुगतान करता है। अगर आपने भी 31 जुलाई 2024 में रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपके पास अभी भी आखिरी मौका है।

जिन करदाताओं ने जुलाई में आईटीआर फाइल नहीं किया है वह 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटिड रिटर्न (Belated ITR) फाइल कर सकते हैं। इस रिटर्न फाइल करने के साथ उन्हें

पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। अगर वह इस समयसीमा तक भी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।

क्या होता है बिलेटिड रिटर्न

टैक्सपेयर आईटीआर फाइल करने पर चूक जाते हैं तो उनके पास लेट रिटर्न फाइल करने का मौका होता है। वह 31 दिसंबर 2024 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बिलेटिड रिटर्न फाइल करने पर उन्हें लेट फीस का भुगतान करना पड़ता है। अगर करदाता बिलेटिड रिटर्न भी फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। इसके अलावा आयकर विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है।

कितना देना होगा जुर्माना?

जिन टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपये से कम हैं उन्हें 1,000 रुपये लेट फीस देनी होगी। वहीं, 5 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर 5,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी।

बिलेटिड रिटर्न कैसे भरें?

सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट के ई-फाइलिंग पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login) पर जाएं।

अब पैन नंबर (Pan Number) की मदद से e-Filing Portal पर लॉग-इन करें।

इसके बाद अपने इनकम सोर्स के हिसाब से सही आईटीआर फॉर्म का सेलेक्शन करें।

अब FY2023-24 के लिए असेसमेंट ईयर 2024-25 को सेलेक्ट करें।

इसके बाद करदाता को इनकम, टैक्स डिडक्शन (Tax Deduction) और बकाया आदि की जानकारी देनी होगी।

अब बकाया ब्याज और जुर्माने आदि का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें।

आईटीआर फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई जरूर करें। Aadhaar ओटीपी, नेट बैंकिंग के जरिये आईटीआर वेरिफाई करें। आपको बता दें कि आईटीआर वेरिफाई किए बिना रिटर्न मान्य नहीं होगा।

बिकवाली भरे बाजार में गिर गए टॉप-10 फर्म के एम-कैप, RIL को हुआ तगड़ा नुकसान

शेयर बाजार में पिछले हफ्ते पांचो दिन गिरावट देखने को मिला था। इस गिरावट भरे कारोबार में बाजार की टॉप-10 कंपनियों के एम-कैप गिर गए। इन कंपनियों में सबसे बड़ी गिरावट टीसीएस और रिलायंस इंडस्ट्रीज में आई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एम-कैप में गिरावट के बाद भी वह बाजार की टॉप फर्म है। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि पिछले हफ्ते किस कंपनी के एम-कैप में कितनी गिरावट आई।

नई दिल्ली। पिछले सप्ताह के कारोबारी सत्र में शेयर बाजार (Share Market) में भारी गिरावट देखने को मिली थी। इस गिरावट भरे कारोबार का असर ब्लूचिप्स कंपनियों के शेयरों पर पड़ा है। शुक्रवार को दोनों सूचकांक यानी बीएसई और एनएसई 1 फीसदी से ज्यादा गिरकर बंद हुए।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार पिछले हफ्ते दस कंपनियों का संयुक्त एम-कैप 4,95,061 करोड़ रुपये गिर गया। इन दस कंपनियों में सबसे ज्यादा गिरावट टीसीएस, और रिलायंस इंडस्ट्रीज में हुई है।

भारतीय शेयर बाजार में जून 2022 के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई। इस सप्ताह निफ्टी में 4.77 प्रतिशत की गिरावट आई। हफ्ते के शुरुआत में फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर को लेकर फैसला लिया था। फेड के फैसले के कारण बाजार की धारणा काफी बदल गई।

प्रवेश गौड़, वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक, स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड

किस कंपनी का कितना कम हुआ एम-कैप

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का एमकैप 1,10,550.66 करोड़ रुपये घटकर 15,08,036.97 करोड़ रुपये हो गया।

रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) का बाजार मूल्यांकन 91,140.53 करोड़ रुपये की गिरावट के साथ 16,32,004.17 करोड़ रुपये हो गया।

देश के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) का बाजार पूंजीकरण 76,448.71 करोड़ रुपये घटकर 13,54,709.35 करोड़ रुपये रह गया।

भारती एयरटेल (Bharti Airtel) का एम-कैप 59,055.42 करोड़ रुपये घटकर 8,98,786.98 करोड़ रुपये रह गया।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का बाजार पूंजीकरण 43,909.13 करोड़ रुपये कम होकर 7,25,125.38 करोड़ रुपये हो गया है।

पिछले हफ्ते आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) का एमकैप 41,857.33 करोड़ रुपये घटा। अब बैंक का वैल्यूएशन 9,07,449.04 करोड़ रुपये है।

इन्फोसिस (Infosys) का बाजार मूल्यांकन 32,300.2 करोड़ रुपये घटकर 7,98,086.90 करोड़ रुपये हो गया है।

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का बाजार मूल्यांकन 20,050.25 करोड़ रुपये गिरकर 5,69,819.04 करोड़ रुपये रह गया।

हिंदुस्तान यूनिलीवर (Hindustan Unilever) का एमकैप 12,805.27 करोड़ रुपये घटकर 5,48,617.81 करोड़ रुपये हो गया है।

सिर्फ 5 दिन खुलेगा बाजार, क्या इस हफ्ते बाजार में आएगी तेजी?

परिवहन विशेष न्यूज

पिछले हफ्ते शेयर बाजार में बिकवाली भरा कारोबार रहा। ऐसे में निवेशकों की नजर कल से शुरू होने वाले कारोबारी हफ्ते पर बनी हुई है। इस हफ्ते शेयर बाजार में केवल 4 दिन ही ट्रेडिंग होगी। दरअसल क्रिसमस के मौके पर बुधवार को बाजार बंद रहेगा। अगर आप बाजार में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है।

नई दिल्ली। पिछले सप्ताह शेयर बाजार लाल निशान पर ही रहा। शुक्रवार को भी बाजार में करेक्शन हुआ है। इस करेक्शन भरे कारोबार में निवेशकों को नुकसान का सामना करना पड़ा। ऐसे में निवेशकों की नजर साल के आखिरी कारोबारी हफ्ते पर बनी हुई है। जी हां, कल से 2024 का आखिरी कारोबारी हफ्ता शुरू होगा। इस हफ्ते भी कई फैक्टर्स मार्केट की धारणा को प्रभावित करेंगे।

मार्केट एनलिस्ट के अनुसार बाजार के निवेशक ग्लोबल संकेत के साथ विदेशी निवेशकों की चाल पर नजर बनाए रखेंगे। यह बाजार के लिए अहम रहने वाले है। इस हफ्ते शेयर बाजार केवल पांच दिन ही खुलेगा। शेयर बाजार बुधवार को क्रिसमस के मौके पर बंद रहेगा।

शेयर बाजार का अभी कोई बड़ा इवेंट तो नहीं आने वाला है। हालांकि, कुछ वैश्विक आर्थिक संकेत बाजार की धारणा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इनमें से अमेरिकी बांड, डॉलर इंडेक्स परफॉर्मेंसन, जॉबलेस क्लेम, न्यू होम सेल्स डेट आदि शामिल हैं।

प्रवेश गौड़, वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक, स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड

इसके आगे उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशकों द्वारा जारी बिकवाली के कारण बाजार में गिरावट आई है। अगर एफआईआई आउटफ्लो ऐसे ही जारी रहता है तो मार्केट में आगे भी गिरावट रह सकती है।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा कि एफआईआई की रणनीति में खरीदारी से लेकर बिक्री तक के अचानक बदलाव ने बाजार पर असर डाला है। इसके अलावा रुपये-डॉलर के कारोबार और वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की चाल भी बाजार को तय करने में महत्वपूर्ण होगी।

इस हफ्ते केवल पांच कारोबारी दिन बाजार खुलेगा। ऐसे में निवेशक एफआईआई के फ्लो और वैश्विक बाजार प्रदर्शन पर बारीकी से नजर रखेंगे। इसके अतिरिक्त दिसंबर के डेरिवेटिव अनुबंधों के खत्म होने के कारण भी बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है।

सिद्धार्थ खेमका, प्रमुख - अनुसंधान, वेल्थ मैनेजमेंट, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने कहा भारतीय बाजारों के नरम रहने की उम्मीद है और वे अस्थिर माहौल के बीच वैश्विक संकेतों का बारीकी से पालन करेंगे। फेस्टिव सीजन नजदीक आने और 25 दिसंबर को शेयर बाजार में अवकाश सहित वैश्विक बाजार 2-3 दिनों के लिए बंद होने के कारण, इस सप्ताह बाजार गतिविधि कम

पॉपकॉर्न पर लगा तीन तरह का टैक्स तो कई चीजें हुई सस्ती, यहां पढ़ें डिटेल में पूरी बात

परिवहन विशेष न्यूज

शनिवार को हुए जीएसटी बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि इस बैठक में पॉपकॉर्न पर तीन तरह के टैक्स लगाने का फैसला लिया गया। आइए इस आर्टिकल में GST काउंसिल की 55वीं मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली। 21 दिसंबर 2024 (शनिवार) यानी बीते दिन जैसलमेर में GST काउंसिल की 55वीं मीटिंग (55th GST Council Meeting) हुई थी। इस मीटिंग में जीएसटी दरों को लेकर कई फैसले लिए गए हैं। वहीं, कई फैसलों को अगली बैठक के लिए टाल दिया गया है। हम आपको इस आर्टिकल में बता रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल बैठक में क्या फैसला गया।

यूज्ड कारों पर लगेगा ज्यादा कर

GST काउंसिल ने ईवी और यूज्ड कारों की जीएसटी दरों में बदलाव किया है। अब ऑटो कंपनी और डीलर से सेकेंड हैंड ईवी कार खरीदने पर 18 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ईवी कार बेचता है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। वहीं, डीलर ईवी की वैल्यू ऐड करता है तो मार्जिन वैल्यू पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। नई ईवी कार पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।

पॉपकॉर्न पर नहीं लगेगा नया टैक्स

अभी तक पॉपकॉर्न पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इस बैठक में पॉपकॉर्न पर तीन तरह के टैक्स लगाने का फैसला लिया है। अब मिक्स रेडी-टू- ईट पॉपकॉर्न पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12 फीसदी जीएसटी और कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी का जीएसटी लगेगा।

इंश्योरेंस और फूड ऑर्डर पर नहीं हुआ फैसला

हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी कम करने या फिर हटान को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसके अलावा Zomato और Swiggy जैसे बाकी फूड डिलीवरी फूड कंपनी के ऑर्डर पर जीएसटी रेट को कम करने या बढ़ाने पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया। इंश्योरेंस और फूड ऑर्डर के फैसले को टाल दिया गया है।

इसके अलावा बैठक में पेट्रोल-डीजल को जीएसटी दायरे में लाने पर भी चर्चा की गई। इसको लेकर बैठक के सदस्यों ने विरोध जताया। इसका मतलब है कि पेट्रोल-डीजल जीएसटी के दायरे में फिलहाल शामिल नहीं होगा।

डिविडेंड किंग देने वाला है शानदार मौका, साल के चौथे लाभांश पर जल्द लगेगी मुहर

Vedanta Dividend डिविडेंड भी कमाई का शानदार मौका है। वेदांता इस साल का चौथा डिविडेंड देने पर विचार कर रही है। वेदांता को डिविडेंड किंग माना जाता है। पिछले एक साल में डिविडेंड के शेयर ने 100 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। चौथे डिविडेंड की घोषणा से पहले कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का एलान कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर...

नई दिल्ली। डिविडेंड कमाई का शानदार मौका आने वाला है। दरअसल, मार्केट के डिविडेंड किंग के नाम से जानने वाली कंपनी वेदांता लिमिटेड (Vedanta Ltd) साल का चौथा डिविडेंड देने वाली है। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में कंपनी ने निवेशकों को काफी शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी ने लाभांश के लिए रिकॉर्ड डेट की जानकारी दे दी है।

कब होगा लाभांश का एलान

कंपनी के बोर्ड मीटिंग 16 दिसंबर 2024 (सोमवार) को होगी। इस बैठक में लाभांश के साथ कई और चीजों पर फैसला ले सकती हैं। अगर बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड को मंजूरी मिलती है, तो ज्लद ही निवेशक को डिविडेंड मिल जाएगा।

क्या है रिकॉर्ड डेट 2024

सोमवार को वेदांता के शेयर में फोकस में रहेंगे। एक्सपर्ट के अनुसार सोमवार को कंपनी के शेयर में तेजी आ सकती है। अगर डिविडेंड को मंजूरी मिलती है तो रिकॉर्ड डेट 24 दिसंबर 2024 होगा। जी हां, कंपनी ने 24 दिसंबर रिकॉर्ड डेट तय किया है। रिकॉर्ड डेट के अनुसार जिन शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट (Demat Account) में 24 दिसंबर 2024 तक कंपनी के शेयर होंगे, उन्हें ही डिविडेंड मिलेगा।

शेयर ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न

वेदांता के शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर ने पिछले एक साल में 100 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। वेदांता का मार्केट कैपिटलाइजेशन (Vedanta M-Cap) लगभग 1.93 लाख करोड़ रुपये है। मार्केट एक्सपर्ट ने वेदांता शेयर प्राइस का टारगेट (Vedanta Price Target) '600 रुपये प्रति शेयर' और 'रेटिंग' खरीद किया है।

टॉप-10 में से 5 कंपनियों के एम-कैप में हुई बढ़त, भारतीय एयरटेल रहा टॉप गेनर

शेयर बाजार के टॉप फर्म का खिताब रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। पिछले सप्ताह भले ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के एम-कैप में गिरावट आई है। इसके बावजूद वैल्यूएशन के हिसाब से टॉप फर्म है। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव भरा कारोबार रहा। इस उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बीच टॉप-5 कंपनियों के एम-कैप में गिरावट आई है। इस आर्टिकल में जानते हैं कि बाजार के टॉप-10 फर्म की रैंकिंग क्या है।

नई दिल्ली। पिछले सप्ताह शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बीच स्टॉक मार्केट की टॉप-10 कंपनियों में से 5 फर्म के एम-कैप में शानदार तेजी आई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार इन पांच फर्म के एम-कैप 1,13,117.17 करोड़ (1.13 लाख करोड़)रुपये बढ़े हैं। सबसे ज्यादा बढ़त भारती एयरटेल के एम-कैप में हुआ है।

बढ़ गया इनका एम-कैप

- पिछले सप्ताह भारती एयरटेल का बाजार मूल्यांकन 47,836.6 करोड़ रुपये बढ़कर 9,57,842.40 करोड़ रुपये हो गया।
- इन्फोसिस का बाजार मूल्यांकन 31,826.97 करोड़ रुपये चढ़कर 8,30,387.10 करोड़ रुपये हो गया।
- एचडीएफसी बैंक का एम-कैप 11,887.78 करोड़ रुपये बढ़कर 14,31,158.06 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,760.8 करोड़ रुपये की बढ़त के साथ 9,49,306.37 करोड़ रुपये हो गया।
- टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 9,805.02 करोड़ रुपये बढ़कर 16,18,587.63 करोड़ रुपये हो गया।

घट गए इन कंपनियों के एम-कैप

- रिलायंस इंडस्ट्रीज का एमकैप 52,031.98 करोड़ रुपये घटकर 17,23,144.70 करोड़ रुपये रह गया।
- एलआईसी का बाजार मूल्यांकन 32,067.73 करोड़ रुपये घटकर 5,89,869.29 करोड़ रुपये हो गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार पूंजीकरण 22,250.63 करोड़ रुपये कम होकर 5,61,423.08 करोड़ रुपये रह गया।
- भारतीय स्टेट बैंक का एमकैप 2,052.66 करोड़ रुपये की गिरावट के साथ 7,69,034.51 करोड़ रुपये हो गया।
- आईटीसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,376.19 करोड़ रुपये कम होकर 5,88,195.82 करोड़ रुपये रह गया।

टॉप-10 फर्म की रैंकिंग

इंडियन स्टॉक मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे मूल्यवान कंपनी रही। इसके बाद टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, भारतीय स्टेट बैंक, एलआईसी, आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर आती हैं।

'नियम तोड़े, तो छोड़ेंगे नहीं...', बाल विवाह पर हिमंत सरकार सख्त; एक ही रात में 416 लोगों को किया गिरफ्तार

बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार लगातार सख्ती दिखा रही है। असम पुलिस ने बाल विवाह से जुड़े मामलों में बीती रात 416 लोगों को गिरफ्तार किया और 335 मामले दर्ज किए। गिरफ्तार किए गए लोगों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। मामले पर सीएम सरमा ने कहा कि हम इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए साहसिक कदम उठाते रहेंगे।

गुवाहाटी। बाल विवाह के खिलाफ असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार सख्ती से पेश आ रही है। इसके खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत असम पुलिस ने बीती रात 416 लोगों को गिरफ्तार किया और 335 मामले दर्ज किए। गिरफ्तार किए गए लोगों को आज अदालत में पेश किया जाएगा।

बाल विवाह जैसी बुराई खत्म करके रहेंगेः हिमंता

बाल विवाह को लेकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का पोस्ट भी सामने आया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, असम बाल विवाह के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखे हुए है। बीती रात को शुरू किए गए तीसरे चरण के अभियान में 416 गिरफ्तारियां की गईं और 335 मामले दर्ज किए गए। गिरफ्तार किए गए लोगों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। हम इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए साहसिक कदम उठाते रहेंगे।

घुसपैठियों को बाहर करेंगेः सरमा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि राज्य सरकार असम के लोगों की पहचान को बनाए रखने और उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, ₹सरकार घुसपैठियों के प्रभाव को सीमित करने के लिए परिसीमन की दिशा में भी काम कर रही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 10,000 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है।

शहीद खड़गेश्वर तालुकदार को किया याद

असम आंदोलन के पहले शहीद खड़गेश्वर तालुकदार के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके बलिदान ने राज्य के साथ-साथ पूरे देश में शोक की लहर पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि खड़गेश्वर तालुकदार से प्रेरित होकर 800 से अधिक अन्य शहीदों ने भी राज्य के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। मुख्यमंत्री सरमा ने यह भी कहा कि असम आंदोलन असम और उसके लोगों को अवैध प्रवास के अभिशाप से बचाने के संकल्प की अभिव्यक्ति था।

सरकार मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा करती रहेगी

इससे पहले 10 दिसंबर को सोनितपुर जिले के जमुरीहाट में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित स्वाहिद दिवस समारोह में भाग लेते हुए सीएम सरमा ने कहा कि असम सरकार मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने असम आंदोलन में जाति, माटी और भेटी के सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को भी श्रद्धांजलि दी।

साम्बादिक रूबेन बानार्जी ने पांडियन का गोंद खोला

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर: रूबेन बनर्जी की किताब के बारे में बात करें। रूबेन ने बीजेडी की हार का कारण लिखा है। रूबेन बनर्जी की किताब में पांडियन का गुमर। पांडियन के उद्भव और प्रभाव को पुस्तक में दर्शाया गया है। 2018 के बाद पांडियन का प्रभाव बढ़ गया। पांडियन ने सरकार संभाली।2019 में, पांडियन बीजे के चुनाव कक्ष का प्रबंधन कर रहे थे। 2024 में पांडियन स्वयं अभियान में उतरे। 2024 में कमरे का प्रबंधन करने वाला कोई नहीं था। कुप्रबंधन के कारण टीम हार गई। पार्टी के अंदर कई नेताओं ने पांडियन का विरोध किया। बिजेड़ी लोग पांडियन को एक बुद्धिमान फूल कहते थे।

"तस्करी के लिए हाइटेक ड्रोन्स और तकनीक का इस्तेमाल कर रहा पाकिस्तान"

सभी जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद का गढ़ है। पाकिस्तान न केवल आज दुनिया में आतंकवाद फैला रहा है बल्कि वह स्वयं भी इससे बहुत त्रस्त है। हाल ही में उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक सुरक्षा चौकी पर बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, मीडिया के हवाले से खबरें आईं हैं कि आतंकवादियों की ओर से किए गए इस भीषण हमले में 16 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। मीडिया से यह भी सूचना मिली है कि पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा बलों पर हुआ सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है।न केवल आतंकवाद बल्कि पाकिस्तान अपने यहां से नशा व हथियारों की तस्करी का भी आज एक बड़ा गढ़ ही है। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज पाकिस्तान ड्रग्स व हथियारों की स्मगलिंग के लिए ऐसे हाईटेक ड्रोनों का इस्तेमाल कर रहा है, जो आसानी से पकड़ में नहीं आते। गौरतलब है कि जहां नशीली दवाओं की तस्करी अक्सर अपराध के अन्य रूपों जैसे-आतंकवाद, मनी लॉनड्रिंग अथवा भ्रष्टाचार से जुड़ी होती है, वहीं दूसरी ओर हथियारों की तस्करी आतंकवाद व आतंकी घटनाओं को जन्म देती है।कहना ग़लत नहीं होगा कि आज नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी से राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा है। नशा व हथियार तस्करी ही नहीं धार्मिक शिक्षा के नाम पर भी पाकिस्तान आज एक खतरनाक खेल, खेल रहा है। पाठकों को बताता चलूं कि हाल ही में पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और खुफिया एजेंसी आइएसआइ के गठजोड़ का भी एक फ्रांसीसी पत्रिका 'ले स्पेक्टेकल डू मोंड' द्वारा यह खुलासा किया गया है कि पाकिस्तान जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को सेना की तरह प्रशिक्षित कर रहा है और धार्मिक शिक्षा के नाम पर साज़िश रच रहा है। यह बहुत ही खतरनाक है कि आज जैश धार्मिक शिक्षा की आड़ में आतंकी तैयार कर रहा है। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज पाकिस्तान धार्मिक शिक्षा की आड़ में आतंकी ही तैयार नहीं कर रहा है अपितु वह भारत में हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी के नये-नये तरीके खोज रहा है और उन्हें इस्तेमाल में ला रहा है। सच तो यह है कि पाकिस्तान स्थित विभिन्न आतंकवादी समूह आज डिजिटल यानी कि विभिन्न आनलाइन गतिविधियों के जरिए भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने में लिप्त है। हालांकि, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, हमारे देश की साइबर टीम और हमारे तमाम सुरक्षा बिल इसको लेकर पहले से ही बहुत सतर्क और मुस्तैद हैं। बावजूद इसके भारत को पाकिस्तान द्वारा की जा रही डिजिटल घुसपैठ को रोकने के लिए और बड़े कदम उठाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आज का जमाना सूचना क्रांति का है।हम सभी जानते हैं कि आज आनलाइन माध्यमों से पलों में भारत विरोधी कंटेंट को इधर से उधर पहुंचाया जा सकता है। आज तस्कर और आतंकी लगातार तकनीक और मोबाइल क्रांति का सहारा ले रहे हैं। सच तो यह है कि मोबाइल और तकनीक के इस्तेमाल ने आतंकियों/तस्करों/ माफियाओं के लिए तस्करी के तरीके, रास्ते सटीक और आसान बना दिए हैं। आलम यह है कि अब सरहद के पास कोई स्थान विशेष को निर्दिष्ट करके हथियार और हेरोइन, अफीम, गांजा ,चरस, नशीली दवाएं आदि मादक पदार्थ तथा हथियार तक गिराए जाते हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान, भारत समेत विश्व के अनेक देशों में हथियारों और नशीले पदार्थों की खपत करता है। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में सालाना 44 टन तक संसाधित हेरोइन की खपत होती है। पड़ोसी अफ़गानिस्तान से 110 टन हेरोइन और मॉर्फिन की तस्करी पाकिस्तान के ज़रिए अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में की जाती है। इसके अलावा, माना जाता है कि पाकिस्तान का अवैध ड्रग व्यापार सालाना 2 बिलियन डॉलर तक कमाता है। आज पाकिस्तान ड्रोन से अवैध रूप से ड्रग्स कारोबार में लिप्त है।आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2024 के दस महीनों में ही पाकिस्तान से पंजाब सीमा पर भेजे गए 177 ड्रोन बरामद किए गए हैं। यह बरामदगी 2023 में पकड़े गए ड्रोन की संख्या से 107 अधिक है। गत वर्ष 60 ड्रोन बरामद हुए थे। वर्ष 2022 में जून के महीने में यह सामने आया था कि पाक के तस्कर पंजाब सीमा से सटे खेतों व बॉर्डर फेंसिंग के पास नशे से भरी ईंटें फेंक रहे हैं। उस वक्त यह भी सामने आया था कि पानी की मोटरों में इस्तेमाल होने वाले होलो पंप में भी नशा भरकर सीमा पार से भेजा जा रहा है और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों का भी इस्तेमाल नशा तस्करी में किया जा रहा है। पिछले कुछ समय पहले यह भी सामने आया था कि अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट भारत में नशे की खेप लाने के लिए अलग-अलग रास्तों का फायदा उठा रहे हैं। मसलन, गुजरात का मुंद्रा पोर्ट, पंजाब बॉर्डर, नेपाल और म्यामांर के रास्ते भारत में ड्रग्स लाई जा रही है। वाकई यह बहुत ही संवेदनशील है कि आज भारतीय तस्कर पाकिस्तानी तस्करों को लोकेशन भेज ड्रोन के माध्यम हेरोइन, गांजा, चरस और असलहा आदि की खेप मंगवा रहे हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि पाक तस्करों का समर्थन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ भी करती है। आइएसआइ इन्हीं तस्करों की मदद से भारत में विस्फोटक सामग्री, हथियार व नशीले पदार्थों तक को भिजवाती है। सच तो यह है कि पाकिस्तान भारत में शांति व सौहार्द को भंग करने के उद्देश्य से चोरी-छुपे हथियारों की सप्लाई के साथ नशा तस्करी को भी अंजाम दे रहा है और यही कारण है कि भारत में तस्करी आज एक बड़ी समस्या के रूप में उभरकर सामने आ रही है, जो सिर्फ कानून व्यवस्था पर ही नहीं, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति, हमारे समाज और पर्यावरण, स्वास्थ्य पर भी कहीं न कहीं बुरा असर डाल रही है। कहना ग़लत नहीं होगा कि तस्करी का प्रभाव केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहता। यह पूरे देश की सुरक्षा, स्वास्थ्य, समाज और पर्यावरण तक को प्रभावित करता है। पाकिस्तान अपनी धरती से भारत विरोधी गतिविधियों का संचालन करता रहा है और आज भी वह लगातार ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है। तस्करी की बात करें तो हाल ही में पंजाब के अमृतसर (ग्रामीण) में पुलिस ने 4 किलो हेरोइन के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस हेरोइन को पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए तस्करी करके लाया गया था। हेरोइन ही नहीं पुलिस ने एक 9 एमएम पिस्तौल भी बरामद की है। आज भी नेपाल और पंजाब के रास्ते पाकिस्तान से हेरोइन और अफीम जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी की जाती है और इस आशय की खबरें मीडिया के माध्यम से आतीं रहतीं हैं। दो साल पहले एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक के हवाले से यह खबरें आईं थीं कि पाकिस्तान, अपने हितैषी चीन में बने नये ड्रोन के स्थान पर अब पाकिस्तान में ही बनाए गए पुराने ड्रोन तस्करी के लिए इस्तेमाल कर रहा है।सूत्रों के मुताबिक भारतीय सुरक्षा बलों की पाकिस्तानी तस्करों पर लगातार कार्रवाई और महंगे चीनी ड्रोन से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए पाकिस्तान द्वारा ऐसा किया जा रहा है। गौरतलब है कि पाकिस्तान से भारतीय सीमा में आने वाले ज्यादातर ड्रोन चीन में ही बने होते हैं, जिनमें हेक्साकॉप्टर और क्वाडकॉप्टर ड्रोन भी शामिल हैं। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि पाकिस्तान आज ज्यादातर अपने देश में बने ड्रोन से ही हथियार और नशा भारत में सप्लाई कर रहा है। आज हमारे देश की सीमा सुरक्षा एजेंसियाँ, सीमा सुरक्षा बल और सीमा शुल्क अधिकारी, पाकिस्तानी तस्करों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करते हैं, अनेक ड्रोनों को उन्होंने मार गिराये हैं और तस्करों को पकड़ा भी हैं,जिसके परिणामस्वरूप अवैध व्यापार अस्थायी रूप से रुका भी है।हालाँकि, यह बात अलग है कि तस्करी में शामिल लोग अपने अवैध व्यापार (नशीले पदार्थों, हथियारों की सप्लाई) को जारी रखने के लिए वैकल्पिक मार्गों के साथ ही तस्करी के अन्य विकल्पों की तलाश करते हैं। आज पाकिस्तान आतंकियों, तस्करों की सहायता से देश के अंदरूनी इलाकों में अव्यवस्थाओं को फैलाने की कोशिश करता है और इसके लिए वह सूचना क्रांति के इस दौर में नये-नये हथकंडे अपना रहा है। यह बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है कि आज पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकियों और नशा माफिया/तस्करों ने अपनी गतिविधियों के पुराने तरीकों को छोड़कर नये तरीके अपना लिए हैं। आज पाकिस्तान से पाकिस्तानी सिम कार्ड की रेंज बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी आतंकी और तस्कर आज वाट्सएप व पाकिस्तानी सिमकार्ड से भारतीय तस्करों से संपर्क साधते हैं, क्योंकि अब रेंज बढ़ाये जाने से पाक मोबाइल कंपनियों का सिग्नल सीमावर्ती भारतीय गांवों तक पहुंचने लगा है।कहना ग़लत नहीं होगा कि अब सीमा पर पूरे षड्यंत्र के साथ तस्करी (हेरोइन, गांजा,चरस, नशीली दवाओं और असलहा की खेप)और आतंकी गतिविधियां हो रही हैं। अक्सर तस्कर आपस में कोड वर्ड देकर एक दूसरे से मादक पदार्थ व हथियार मंगवाते हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि तस्करी के काम में ज्यादातर बेरोजगार युवा जुड़े हुए हैं। यहां तक कि इस कारोबार में आजकल युवतियां भी शामिल हो गई हैं। अमूमन होता यह है कि लड़कियों/महिलाओं पर पुलिस, सेना, सुरक्षा बल शक नहीं करते हैं और वे इनकी गिरफ्त में आने से अक्सर बच जाते हैं। आज भारतीय सरहद में ऐसे बहुत से गांव हैं, जिनमें खेत आधे भारतीय सरहद में और आधे पाकिस्तानी सरहद में है, तस्कर विभिन्न कृषि गतिविधियों के ज़रिए इसका फायदा उठाते हैं। यह संवेदनशील और गंभीर है कि आज नशा तस्करी के लिए अब ऑनलाइन प्लेटफार्म का भी इस्तेमाल हो रहा है।बहरहाल, भारत ड्रोन व सूचना क्षेत्र में क्रांति के मार्ग पर अग्रसर हो गया है। भारत में आज सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत पुख्ता और सख्त है।बावजूद इसके पाकिस्तान की ओर से नशे व हथियारों की तस्करी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा। अतः इसका मुकाबला करने के लिए हमें नई रणनीतियों को बनाने की जरूरत है।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर

नजीराबाद पुलिस की सक्रियता से कानपुर में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ ,आधा दर्जन गिरफ्तार

- पहले भी अनेक वारदातों को अंजाम दे चुके शातिर अपराधी आधा दर्जन चोरों से 10 वाहन बरामद, अन्य की तलाश में जुटी पुलिस

सुनील बाजपेई

कानपुर। यहां कानून और शांति व्यवस्था के पक्ष में अपराधियों के खिलाफ लगातार सफल मोर्चा खोले नजीराबाद पुलिस को वाहन चोरों के एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ करने में सफलता मिली है। उसने इस गिरोह के आधा दर्जन सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 10 मोटरसाइकिल बरामद की है। अब गिरोह के अन्य सदस्यों की भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है ,जिनके पास से भी कई वाहन बरामद हो सकते हैं। पकड़े गए चोरों में एक नाबालिक भी शामिल है।

पुलिस द्वारा अब तक की गई पूछताछ से निकले निष्कर्ष के मुताबिक इस गैंग से और लोग भी जुड़े हो सकते हैं। अन्य वाहनों की रिकवरी का भी प्रयास किया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार वाहन चोरी करने के लिए गिरोह के सभी लोग एक साथ निकलते और चेन बनाकर वाहनों की रेकी करने के बाद घटना को अंजाम देते थे।

याद रहे कि जिस थाने नजीराबाद पुलिस को वाहन चोरों के इस शातिर गिरोह का सटीक भंडाफोड़ करने में सफलता मिली है। आजकल उस नजीराबाद थाने की कमान हर तरह के अपराधियों के खिलाफ लगातार सफल मोर्चा खोले निर्दोष फंसे नहीं और अपराधी बचे नहीं जैसी लोकहित की प्रबल विचारधारा के अनुरूप अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और पीड़ितों की हर संभव सहायता में भी अग्रणी निष्पक्ष और पारदर्शी कार्यशैली के भगवान और भाग्य यानी कर्म भरोसे रहने वाले तेजतर्रार, व्यवहार कुशल प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर अमान सिंह के हाथ में है।

कानून और शांति व्यवस्था के पक्ष में अपराधियों के खिलाफ चुनौतीपूर्ण नजीराबाद की भी कमान बहुत सफलता पूर्वक संभाले और सभी संगीन घटनाओं का सटीक खुलासा करते हुए अपनी जुझारू नौकरी के अबतक कार्यकाल में सैकड़ों अपराधियों को जेल की हवा खिला चुके जुझारू इंस्पेक्टर अमान सिंह के अब तक के कार्यकाल के विवेचन से यह भी साबित होता है कि हालात चाहे जैसे रहे हों लेकिन उन्होंने अपनी कर्तव्य के प्रति निष्ठा के साथ समझौता आज तक नहीं किया।

इसी के साथ इंस्पेक्टर अमान सिंह की कार्यशैली भी संभ्रांत असहाय लोगों की हितरक्षक और बहुत मैत्रीपूर्ण भी मानी जाती है ,जिसके अनुरूप ही वह जहां उचित पात्र लोगों की हर संभव सहायता करते हैं। वहीं कानून और शांति व्यवस्था के पक्ष में अपराधियों के खिलाफ शठे शाठ्यम समाचरेत वाली कहावत चरितार्थ करने से भी नहीं चूकते। यही वजह है कि इंस्पेक्टर अमान सिंह की कर्तव्य के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा उनकी जुझारू नौकरी के अब तक के कार्यकाल में सभी संगीन घटनाओं का सटीक खुलासा करते हुए दर्जनों शातिरों को सबक सिखाने में भी सफल हो चुकी है,जिसके क्रम में वाहन चोर गिरोह के सदस्यों समेत फरार चल रहे अन्य अपराधियों की भी तलाश लगाता जारी है।

पांच दिवसीय भारतीय ज्ञान प्रणाली को आधुनिक शिक्षा में एकीकृत करने के विषय पर राष्ट्रीय संकाय विकास कार्यक्रम का सफल समापन

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा द्वारा आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) "आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रणालियों को एकीकृत करना: एनईपी-2020 परिप्रेक्ष्य" का समापन हुआ। यह कार्यक्रम 16 से 20 दिसंबर, 2024 तक चला, जिसमें देशभर के शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और प्रबुद्ध व्यक्तियों ने भाग लिया।कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शैक्षणिक और प्रशासनिक विकास केंद्र के तत्वाधान में किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान प्रणालियों की प्राचीन परंपराओं और आधुनिक शिक्षा में उनकी प्रासंगिकता को समझना और उनका समावेश करना था।प्रोफेसर प्रीती मेहता, डायरेक्टर ने बताया कि पांच दिनों तक चले इस कार्यक्रम में 10 सत्र आयोजित किए गए, जिनका नेतृत्व विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने किया। इन सत्रों में प्रबंधन, मानविकी, चिकित्सा विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई। विभिन्न सत्रों के प्रमुख वक्ताओं में प्रो. करुणेश सक्सेना , प्रो .कश्मीर भट्ट (एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा), प्रो.पीएम मिश्रा रिटायर्ड प्रोफेसर देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर) प्रो. रश्मि सक्सैना (गवर्नमेंट पीजी कॉलेज खेरवाड़ा), श्री अनिल सक्सेना (वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार), डॉ सुरेंद्र पीपलीवाल वरिष्ठ सलाहकार,(जिम्मी धन्वंतरी हॉस्पिटल कांकरोली)प्रो. अशोक कुमार गुप्ता (रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा) ने भारतीय ज्ञान प्रणालियों के आधुनिक शिक्षा में योगदान और उनके अनुप्रयोग पर जोर दिया।समापन समारोह के मुख्य अतिथि प्रो. रमेश शारदा , (स्पीयर्स स्कूल ऑफ बिजनेस, ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी, यू एस ए) ने अपने संबोधन में कहा, "भारतीय ज्ञान परंपरा, जो हमारे समृद्ध इतिहास का अभिन्न हिस्सा है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में एक नई दिशा प्रदान कर सकती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो. अरुण कुमार, (वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय) ने की, उन्होंने भारतीय परंपराओं और आधुनिक शिक्षा के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया।विशिष्ट अतिथि के रूप मे डॉ. एस.एन. मोदानी वाइस चेयरमैन संगम समूह ने समृद्ध भारतीय वैदिक संस्कृति का व्यक्ति के जीवन में महत्व पर अपने विचार रखे।

संगम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. करुणेश सक्सेना एवं प्रो. राजीव मेहता (कुलसचिव) ने कार्यक्रम की सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए सभी प्रतिभागियों और आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने कहा, "यह पहल भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी और शिक्षकों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगी।" शिक्षकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम उनके लिए प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक रहा।समापन सत्र में, प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम के अंत में प्रोफेसर मानस रंजन (उप कुलपति) ने इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। यह कार्यक्रम भारतीय शिक्षा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ. सीमा काबरा एवं डॉ.श्वेता बोहरा ने किया।

झारखंड में अफीम तस्करों की संपत्ति होगी जब्त, गृह सचिव व डीजीपी की खेती पर कड़ा रुख

बंदगांव में अफीम के खिलाफ एस डी ओ का जन-जागरण

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची, झारखंड के जंगली इलाकों में अब अफीम , खसखस (पोस्तो) की खेती करना माओवादी ग्रस्त इलाकों, व्यवसाय में लगे तस्करों, इससे जुड़े प्रभावी चेहरों के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी .विगत एक दशक से निरीह जंगली किसानों के जरिए यह कृषि व व्यवसाय काफी फल फूल रहा है । इस बाबत झारखंड की गृह सचिव वंदना दादेल और पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने मंगलवार को संबंधित अधिकारियों से अफीम की खेती के खिलाफ चल रहे अभियान में तेजी लाने और तस्करों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने को कहा है . झारखंड पुलिस पिछले कुछ दिनों से अफीम की खेती के खिलाफ अभियान चला रही है और पलामू तथा खूंटी समेत विभिन्न जिलों में सैकड़ों एकड़ भूमि पर लगे अफीम के पौधों को नष्ट किया गया है तथा हर वैसे जिला जहां इस अवैध फसल उत्पादन होता तथा विपणन किया जाता वाहां के उपायुक्तों एवं जिला पुलिस को सख्त निर्देश दिया गया है

श्रीमती बंदना दादेल तथा डी जी पी अनुराग गुप्ता ने चतरा का दौरा किया है, जहां चार जिलों चतरा, हजारीबाग, लातेहार और रांची के पुलिस, वन, कृषि और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अभियान की समीक्षा के लिए बैठक की. दादेल ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जहां भी अफीम की खेती दिखे, उसे संबंधित विभागों के साथ समन्वय करके नष्ट कर दिया जाए. गुप्ता ने कहा कि अफीम की खेती में शामिल लोगों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है. उन्होंने कहा, बड़ी मछलियों को पकड़ने की जरूरत है. अफीम तस्करी के जरिए बड़ी संपत्ति अर्जित करने वालों की संपत्ति जब्त की जाएगी.

झारखंड की गृह सचिव वंदना दादेल और पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने मंगलवार को संबंधित अधिकारियों से अफीम की खेती के खिलाफ चल रहे अभियान में तेजी लाने और तस्करों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने को कहा. अधिकारियों ने कहा कि झारखंड पुलिस पिछले कुछ दिनों से अफीम की खेती के खिलाफ अभियान चला रही है और पलामू तथा खूंटी समेत विभिन्न जिलों में सैकड़ों एकड़ भूमि पर लगे अफीम के पौधों को नष्ट किया गया है.

इधर सरायकेला खरसावां जिला जहां कभी बंदना दादेल जिले बीस वर्ष पूर्व प्रथम उपयुक्त रही उस जिलेका उत्तरी हिस्से में स्थित चौका थाना अंतर्गत उलीगुटू व शहरबेडा गांव के जंगल के बीच अनुमंडल पदाधिकारी विकास राय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद सिंन्हा ने चौक थाना पुलिस एवं एस एस कंपनी कमांडर के साथ मिलकर 5 एकड़ में अफीम खेती को नष्ट किया गया । वही सिंहभूम का सर्वाधिक प्रभावित इलाका टेबो, झरझरा , बंदगांव आदि में उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम के निर्देश पर एस डी एम चक्रधरपुर के जरिए माओवादी प्रभावित इलाका रहा इन गांव गांव में अफीम खेती के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है । उधर सप्ताह चौंका इलाके के एक व्यक्ति को सरायकेला ए डी जे -1, न्यायालय से 10 वर्ष की सजा मिली है । उसके पूर्व में भी 20 वर्ष की सजा एन डी पी आर एस एक्ट के तहत से सरायकेला खरसावां व्यवहार न्यायालय ने सुनाई है ।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023